रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक
अलग पहचान
सत्य की उड़ान

गुरुवार
16 जुलाई -2026
वर्ष 10, अंक 312
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

पेज-8

संक्षिप्त समाचार

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील लागू

- सस्ती हो गईं व्हिस्की, रम, वोडका, लग्जरी कारें और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स

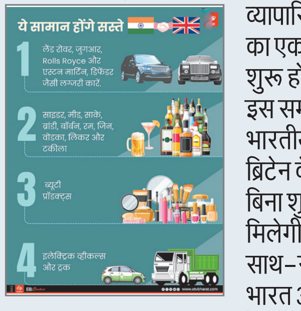
ये सामान होंगे सस्ते
1 लैंड रोवर, जगुआर, Rolls Royce और एस्टन मार्टिन, डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें
2 साइडर, मीड, साके, ब्रांडी, बॉर्बन, रम, जिन, वोडका, लिकर और टकीला
3 ब्यूटी प्रॉडक्ट्स
4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और ब्रिटेन के बीच आज बुधवार 15 जुलाई 2026 से व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) लागू हो गया है। इस एग्रीमेंट के लागू होते ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। इस समझौते से भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच मिलेगी। इसके साथ-साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले कई प्रॉडक्ट पर उत्पाद शुल्क भी चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा। इससे कृषि, उद्योग, सेवा सेक्टर, एमएसएमई और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की संभावना है। दोनों देशों के लिए यह डील काफी अहम मानी जा रही है, जो दोनों देशों के व्यापार को एक नई दिशा देने का काम करेगी।

अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, 30 की मौत

सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, करीब सात घंटे तक चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं।

ममता बनर्जी को एक और झटका

टीएमसी विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल

कोलकाता (एजेंसी)। टीएमसी विधायक मदन मित्रा बुधवार को विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बागी खेमे में शामिल हो गए। मदन को पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है. मदन मित्रा जाने के साथ ही पार्टी के अंदर चल रही अनबन और गहरी हो गई है। कमरहाटी के विधायक मित्रा ने घोषणा की कि उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी के तहत काम करने वाली सभी राष्ट्रीय और राज्य कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है।

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी मेसरा ने मनाया 72वां स्थापना दिवस

- NVIDIA -पावर्ड सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की घोषणा की
- नया सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, एआई रीसर्च और पूर्वी भारत से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भावी प्रतिभा को बनाएगा मजबूत

दैनिक अलग पहचान
डेस्क संवाददाता

रांची। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, मेसरा ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर 1955 से चली आ रही अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, इनोवेशन और राष्ट्र-निर्माण की विरासत का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के लीडरों, पूर्व छात्रों, फैकल्टी सदस्यों, छात्रों और विशेष अतिथियों ने हिस्सा लिया तथा बीआईटी मेसरा की यात्रा और भारत में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एप्लाइड साइंसेज़ की शिक्षा को आकार देने में इसकी भूमिका पर विचार-विमर्श किया।

स्थापना दिवस समारोह में झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, उनके साथ आईआईटी भुवनेश्वर के निदेशक प्रो. एस. करमलकर और टेगा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मदन मोहनका अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।

स्थापना दिवस के इस अवसर पर, बीआईटी मेसरा ने संस्थान की एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रीसर्च क्षमताओं को बढ़ाने के लिए NVIDIA -पावर्ड सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की घोषणा की। यह सेंटर हाई-परफॉर्मेंस जीपीयू-बेस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, वीएलएसआई, ड्रग डिस्कवरी, प्रेसिजन एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और अन्य उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्योग जगत के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा।

यह घोषणा भविष्य की तैयारी को लेकर बीआईटी मेसरा के बड़े एजेंडा को दर्शाती है। इसका उद्देश्य रीसर्च इकोसिस्टम को मज़बूत बनाना, अकादमिक एवं उद्योग जगत के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना तथा छात्रों एवं शोधकर्ताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में मिलने वाले मौकों के लिए तैयार करना है। सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में NVIDIA B200 GPUs से पावर्ड आठ हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होंगे।

पुरी रथयात्रा आज से

- 6 महीने पहले से होटल बुकिंग,1500 का कमरा 50 हजार में मिल रहा, हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है

पुरी (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथयात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथयात्रा मार्ग के आसपास के होटल-लॉज की सबसे ज्यादा मांग है। खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़की रथयात्रा मार्ग की ओर खुलती है, उनके लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। पिछले साल के मुकाबले होटल और लॉज का किराया 10 गुना तक बढ़ गया है। जिन लॉज का सामान्य किराया 1500 से 2000 रुपए होता है, उनका किराया रथयात्रा के दौरान तीन दिन के लिए 50 हजार रुपए तक पहुंच गया है। पूरे शहर में करीब 1200 होटल हैं।

- **हावड़ा में प्रोफेसर की गोद बनती है भगवान जगन्नाथ का रथ-** धर्म और आस्था की सीमाओं से परे पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हर साल एक अनोखी रथयात्रा निकाली जाती है। यहां न तो रस्सी से रथ खींचा जाता है और न ही विशाल रथ सजाया जाता है। इसके बजाय कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह को अपनी गोद में लेकर करीब 400 मीटर की परिक्रमा करते हैं। इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदायों के लोग शामिल होते हैं। डॉ. इस्लाम 1992 से भगवान जगन्नाथ पर शोध कर रहे हैं और इस विषय पर 14 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। 1996 से उनके घर में भगवान जगन्नाथ का विग्रह स्थापित है, जबकि 2009 से वे हर साल रथपूजा के अवसर पर इस अनूठी परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं।

- कैबिनेट में हुए 7 बड़े फैसले

बनारस में गंगा किनारे बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, रेल अपग्रेड और सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 15 जुलाई को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मोबाइल फोन प्रोडक्शन तक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर और रेलवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े सात बड़े फैसले हैं। इस पैकेज में सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शामिल हैं, जिन पर कुल 2,19,353 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस ब्रीफिंग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिए गए सात बड़े फैसले पेश कर रहा हूं।

Semicon 2.0 मिशन

- मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
- यूरिया के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी
- पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन का ट्रैक डबलिंग
- डांगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन

वाराणसी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

- कैबिनेट के दो फैसले वाराणसी के विकास को लेकर हैं। ये फैसले बड़े इंफास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं। कैबिनेट ने नेशनल हाईवे-19 (एनएच-19) को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ने वाले 46.039 किलोमीटर लंबे लिंक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है।
- वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे एनएच-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे लिंक के विकास को मंजूरी दी गई है।
- सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में मुख्य कैरिजवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड सहित मुख्य रूप से 6/4-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इसे एनएचएआई द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत कुल 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा।
- एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह कॉरिडोर वाराणसी में भीड़ कम करने की योजना का एक अहम हिस्सा है। यह एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

इंटर्नशिप के लिए पुणे रवाना हुए एमबीआईएनसीटी के विद्यार्थी

महादेवी बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लीनिकल टेक्नोलॉजी

रांची।(टएमबीआईएनसटी) के 28 विद्यार्थी छह माह की क्लीनिकल इंटर्नशिप के लिए पुणे स्थित आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। क्लीनिकल इंटर्नशिप के दौरान उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं, उन्नत चिकित्सकीय प्रक्रियाओं तथा रोगी-केंद्रित देखभाल की व्यावहारिक जानकारी दी जायेगी। साथ ही अनुभवी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का अवसर हासिल होगा।

विद्यार्थियों को रवाना करने के अवसर पर महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लीनिकल टेक्नोलॉजी की प्राचार्या डॉ. सुबानी बाड़ा, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर आशुतोष द्विवेदी, उप-प्राचार्या डॉ. मीनल श्वेता, निरोलिन कुल्लू एवं अंजना मसीह उपस्थित रहीं।

सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान, माननीय महानिदेशक प्रो गोपाल पाठक, कुलपति प्रो सी जगनाथन एवं राज्यसभा सांसद सह निदेशक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉ प्रदीप कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामना संदेश प्रेषित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित अनुभवों के साथ भविष्य में समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे।

महिला की जबरन छाती दबाना, सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं

- पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी किया, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- जज रिसर्च करें, गाइडलाइन पढ़ें

पटना (एजेंसी)। बंद कमरे में जबरदस्ती महिला का सीना दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं है। 9 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए बांका के स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा-जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं। हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की बेंच के सामने में एडवोकेट गुप्ता ने उस केस की सुनवाई के दौरान यह मामला उठाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शुरू किया था। इसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे खींचने की कोशिश करना भी रेप का प्रयास नहीं है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की विशेषज्ञ समिति की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी, जिसमें यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

बेंच ने देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया कि वे इस गाइडलाइन में इस्तेमाल की गई भाषा और अभिव्यक्तियों का सख्ती से पालन करें।

यूपी में दर्दनाक सड़क हादसा

पुलिया से टकराई कार, सिपाही समेत 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक

रायबरेली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के बछरांवा क्षेत्र में बुधवार सुबह लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार के पुलिया की रेलिंग से टकराने से उसमें सवार एक सिपाही समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रुप से घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे लखनऊ से रायबरेली की ओर आ रही कार खेहरनी चौराहे के पास अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे बनी पुलिया की रेलिंग से जा भिड़ी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी पांच लोग वाहन के भीतर फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावां पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हादसे के कारण कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा।

कातिल पत्नी

दूध में दीं नींद की गोलियां

इटावा (एजेंसी)। इटावा के तोड़ा गांव में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया, फिर गला घोंटकर हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

- नहीं कराया तो 3 महीने की जेल, यूसीसी ड्रॉफ्ट में कड़े प्रावधान

मप्र में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्रॉफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। नए मसौदे के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए संबंधित जिले के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन में रहता है, तो उसे अधिकतम तीन महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

माता-पिता को दी जाएगी जानकारी- इस प्रस्तावित कानून के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिव-इन में रहने वाले युवाओं के माता-पिता को उनके रिलेशनशिप स्टेटस की औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थानों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत लिव-इन जोड़ों का पूरा रिकॉर्ड मेनटेन करना होगा। खास बात यह है कि मकान मालिक या पड़ोसी भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे लिव-इन रिलेशनशिप की शिकायत कर सकेंगे।

संपत्ति और उत्तराधिकार के नियमों में बड़ा बदलाव

यूसीसी के इस ड्रॉफ्ट में केवल लिव-इन ही नहीं, बल्कि उत्तराधिकार कानूनों में भी महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए गए हैं। अब तक किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर पत्नी, बच्चों और मां का हक होता था। लेकिन नए कोड के तहत अब पिता को भी बेटे की संपत्ति में बराबर का वारिस माना जाएगा और कानूनी तौर पर उनका हिस्सा तय होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप शुरू करने पर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण और रिश्ता खत्म होने पर उसे औपचारिक रूप से कैंसिल कराना अनिवार्य होगा।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन

रांची, एजेंसी। झारखंड के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 83 वर्षीय मन्नान मल्लिक ने रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार, वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। मन्नान मल्लिक के निधन की खबर से धनबाद समेत पूरे झारखंड और बिहार कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी और धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने भी दुख जताया है।

मवेशियों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए पैसे, चिकित्सक और कर्मचारियों पर आरोप

धनबाद, एजेंसी। बलियापुर स्थित सरकारी पशु अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अस्पताल में पदस्थापित पशु चिकित्सक और दो कर्मचारियों पर चार मवेशियों की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो से की, जिसके बाद विधायक ने मीडिया के सामने कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की। वहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग तेज हो गई है। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि पिछले सप्ताह वज्रपात की घटना में बलियापुर की एक महिला के दो बैल, एक गाय और एक बछड़े की मौत हो गई थी। आपदा राहत योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को पशुओं के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उनसे पैसे मांगे गए। विधायक के अनुसार, महिला कई दिनों तक अस्पताल का चक्कर लगाती रही। मामले को लेकर पंचायत समिति के सदस्य जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद दो कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है और चार पशुओं की मौत से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे समय में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी कथित रूप से अनुचित लाभ के लिए राहत प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच सदाचार समिति भी कर रही है और संबंधित पशु चिकित्सक के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें समिति को मिल चुकी हैं।

जगन्नाथपुर रथ मेला:16 से 25 तक मौसीबाड़ी गोलचक्कर और जगन्नाथपुर बाजार की ओर वाहनों का आना-जाना बंद

रांची, एजेंसी। जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में 10 दिनों के लिए बदलाव किया गया है। 16 से 25 जुलाई तक मौसीबाड़ी गोलचक्कर और जगन्नाथपुर बाजार की ओर सभी प्रकार के वाहनों की इंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। तिरिल मोड़ और शहीद मैदान से मौसीबाड़ी गोलचक्कर तक भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, प्रभात तारा तीनमुहान से जगन्नाथपुर बाजार तक किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। बिरसा चौक से रथ मेला जाने वाले वाहन केवल शहीद मैदान तक ही जा सकेंगे। तुपुदाना और हटिया की ओर से आने वाले वाहन प्रभात तारा मैदान तक ही संचालित होंगे। धुर्वा की ओर से मेला जाने वाले वाहनों को भी प्रभात तारा मैदान तक ही जाने की अनुमति रहेगी। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने इस संबंध में आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। एचईसी और विधानसभा की ओर से आने वाले वैसे वाहन सवार जिन्हें रिंग रोड की ओर जाना हो, वह शहीद मैदान से शालीमार बाजार से धुर्वा गोलचक्कर होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक से रिंग रोड की ओर आना-जाना कर सकेंगे।

डोरंडा कॉलेज की शिक्षिका डॉ अमिया सुरीन का निधन

रांची, एजेंसी। रांची विश्वविद्यालय के डोरंडा कॉलेज में मुंडारी विभाग की नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अमिया सुरीन (48) का इलाज के दौरान सोमवार देर रात निधन हो गया। वह लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थीं। इसके बावजूद मानदेय और नौकरी पर असर पड़ने के डर से हर दिन कॉलेज आ रही थीं। बताया गया कि दो दिन पहले ही उन्हें बिल पास कराने के लिए कॉलेज में खुद उपस्थित होने को कहा गया था। खराब तबीयत के बावजूद वह कॉलेज पहुंचीं। इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गयी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों को उपस्थिति के आधार पर मानदेय मिलता है। इसी वजह से बीमारी के बावजूद डॉ अमिया लगातार कक्षाएं लेने कॉलेज आती रहीं।नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष डॉ त्रिभुवन शाही ने कहा कि डॉ अमिया मानसिक तनाव और बीमारी से जूझ रही थीं।

झारखंड के दो स्टेशन पर अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची । रांची रेल मंडल के लिए 17 जुलाई का दिन खास होने जा रहा है। लंबे समय से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, वह अब करीब है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए स्वरूप में तैयार किए गए पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण 17 जुलाई को प्रस्तावित है। रेलवे ने उद्घाटन समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। दोनों स्टेशनों को सजाया जा रहा है और सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम के संचालन तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे

लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। रेलवे की योजना है कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी हो। इसी वजह से स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आसपास के ग्रामीणों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

अब पहले से बिल्कुल अलग दिखेंगे दोनों स्टेशन

पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन अब पहले जैसे नहीं दिखेंगे। स्टेशन भवन का नया स्वरूप यात्रियों को आधुनिक रेलवे स्टेशन का अनुभव देगा। यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। साफ-सुथरे शौचालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, आकर्षक प्रवेश द्वार और बेहतर रोशनी जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन सुविधाओं का सबसे ज्यादा फायदा आसपास के गांवों से आने वाले यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अब बेहतर और सुविधाजनक स्टेशन मिलेगा।

उद्घाटन से पहले अंतिम तैयारियों में जुटा रेलवे

रेलवे प्रशासन उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। दोनों स्टेशनों पर साफ-सफाई, रंग-रोगन और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं।

डीसीएम श्रेया सिंह ने क्या कहा

रांची रेल मंडल की डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रस्तावित है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और कोशिश है कि यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों के लिए भी यादगार बने। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

रेल नेटवर्क को मिलेगी नई पहचान

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए ये स्टेशन रांची रेल मंडल की नई पहचान बनेंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।

एसी कोच से गायब हो चुके हैं 9.31 लाख बेडरोल

उधर रेलवे के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ट्रेनों के एसी कोच से बड़ी संख्या में बेडरोल गायब होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेनों के एसी कोच से अब तक 9.31 लाख से ज्यादा बेडरोल गायब हो चुके हैं।इनमें तौलिया, चादर, तकिया कवर, कंबल और तकिया जैसी चीजें शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और इससे रेलवे को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

रेलवे ने यात्रियों से की खास अपील

रेलवे ने यात्रियों से साफ कहा है कि एसी कोच में दिया जाने वाला बेडरोल रेलवे की संपत्ति है। यात्रा पूरी होने के बाद उसे कोच में ही छोड़ दें। तौलिया, चादर, कंबल या तकिया अपने साथ ले जाना चोरी की श्रेणी में आता है।रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत सरकारी सामान की चोरी करने पर पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

निगरानी बढ़ाई गई

सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि यह रिपोर्ट केवल रांची मंडल की नहीं, बल्कि देश के विभिन्न रेल मंडलों से जुड़ी केंद्रीय रिपोर्ट है। रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है ताकि रेलवे की संपत्ति सुरक्षित रह सके और सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं लगातार मिलती रहें।

नशे के कारोबार पर प्रहार: दुमका में ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

दुमका, एजेंसी। जिला के हंसडीहा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग पांच ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे के अनुसंधान में जुट गई है।

नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की यह पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरी कार्रवाई है। जिससे इलाके में सक्रिय नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है क्योंकि इस महीने में कुल आठ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो ब्राउन शुगर के कारोबार में लिप्त थे।दरअसल, एसपी के निर्देश पर जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने आज मंगलवार को पगवारा पहाड़ के समीप छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग पांच ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों के नाम हैं- मुन्ताज अंसारी उर्फ लखपतिया, रिजवान अंसारी और फिरोज अंसारी उर्फ ठेउआ। ये हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिंघनी गांव के रहने वाले हैं।

जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर को पता चला कि कुछ युवक पगवारा पहाड़ के समीप ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के साथ-साथ खुद सेवन भी कर रहे हैं। पुलिस के वहां पहुंचते ही तीनों भागने लगे लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। उनकी तलाशी के दौरान तीनों के पास से कुल 4.49 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। जिसमें मुन्ताज के पास 1.91 ग्राम, रिजवान के पास 1.34 ग्राम और फिरोज के पास 1।24 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर तीनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ट्रैफिक जाम से निजात की तैयारी, रांची में जल्द चलेंगी छोटी इलेक्ट्रिक बसें

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची । रांची की सड़कों पर आने वाले दिनों में सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो सकता है। राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग ने छोटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर की संकरी सड़कों, छोटे मोड़ों और लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि बड़ी बसों की तुलना में छोटी ई-बसें आसानी से हर इलाके तक पहुंच सकेंगी और जाम की समस्या भी काफी हद तक कम होगी।

बैठक में बनी सहमति, अब आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

नगर निगम और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों विभाग इस बात पर सहमत हुए कि रांची जैसे तेजी से फैलते शहर के लिए छोटी इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा उपयोगी साबित होंगी। अब बसों के रूट, चार्जिंग स्टेशन, डिपो और टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

नगर आयुक्त बोले, बड़ी बसों को होती है परेशानी

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि शहर के कई मुख्य और संपर्क मार्गों पर बड़ी बसों का संचालन आसान नहीं है। कई जगह सड़कें संकरी हैं और मोड़ इतने छोटे हैं कि बसों को निकालने में दिक्कत होती है। ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।उन्होंने कहा कि छोटी इलेक्ट्रिक बसें इन मार्गों पर बिना किसी बड़ी परेशानी के चल सकेंगी। इससे लोगों को समय पर परिवहन सुविधा मिलेगी और शहर में प्रदूषण भी कम होगा।

पुरानी सिटी बसें बन रही हैं परेशानी की वजह

इस समय रांची नगर निगम करीब ढाई दर्जन सिटी बसों का संचालन कर रहा है। लेकिन इनमें से कई बसें काफी पुरानी हो चुकी हैं। यात्रियों की शिकायत रहती है कि कई बसों की सीटें टूटी हुई हैं, साफ-सफाई ठीक नहीं रहती और कई बार बसें बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं।रोजाना सफर करने वाले लोगों का कहना है कि शहर की आबादी बढ़ने के साथ बसों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मौजूदा व्यवस्था अब शहर की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है।

जहां बड़ी बस नहीं पहुंचती, वहां चलेगी छोटी ई-बस

नगर विकास विभाग ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि ऐसे इलाकों की पहचान की जाए, जहां बड़ी बसें नहीं चल पातीं। अब ऐसे रूट तय किए जा रहे हैं जहां छोटी इलेक्ट्रिक बसें आसानी से लोगों तक पहुंच सकें। इससे शहर के अंदरूनी इलाकों को भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जा सकेगा।

यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं

नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से यात्रियों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है। सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा, बसों के खराब होने की समस्या कम होगी और लोगों को कम खर्च में बेहतर यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक बसें चलने से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी घटेगा, जिससे शहर का वातावरण बेहतर होगा।

रांची की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आएगा नया बदलाव

नगर निगम का मानना है कि छोटी इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

धनबाद दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

धनबाद, एजेंसी। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने दो दिवसीय धनबाद प्रवास के समापन अवसर पर मंगलवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए राजस्व एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के निष्पादन, कार्यालय अभिलेखों, पंजी और सेवा पुस्तिकाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकारी भूमि की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमण के मामलों की नियमित निगरानी करने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट तथा मृत मतदाताओं का त्रुटिरहित सत्यापन कर सूची तैयार करने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी बीएलओ या वालंटियर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, गोविंदपुर अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा, प्रभारी अंचल निरीक्षक नेहा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने कहा- राम मंदिर में चंदा चोरी पर सीएम सख्त, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार

देवघर, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि वह सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपने परिवार, उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों तथा देश की सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। पूजा-अर्चना के बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बासुकीनाथ धाम जाने का भी कार्यक्रम है।

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, जबकि विपक्ष चुनाव परिणामों को लेकर चिंतित रहता है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पार्टी की जीत होने पर विपक्षी दल विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है।

श्रावणी मेला में नहीं होगी नेटवर्क क्रैश और कॉल ड्रॉप की परेशानी, श्रद्धालुओं को मिलेगी कनेक्टिविटी से जुड़ी बेहतर सुविधा!

देवघर, एजेंसी। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य, सुरक्षा और यातायात के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी गई है।

इसी कड़ी में देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं निजी टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेले की शुरुआत से पहले सभी कंपनियां अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ताकि श्रद्धालुओं को नेटवर्क क्रैश, कॉल ड्रॉप या इंटरनेट की धीमी गति जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े

उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में निर्बाध संचार व्यवस्था और हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी कंपनियों को नेटवर्क बैंड विड्थ बढ़ाने और क्षमता अपग्रेड करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक भीड़ के बावजूद मोबाइल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहें।

इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मेले से पहले आवश्यक स्थानों पर अस्थायी मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। इससे भीड़ बढ़ने के बावजूद कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि बीएलओ द्वारा राज्य में 96% मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा चुका है केवल 4 % ही ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाया है (इसमें एएसडीडी सूची के भी मतदाता हो सकते हैं)। ऐसे मतदाता की अधिकता शहरी क्षेत्र में देखी जा रही है, इन शहरी क्षेत्र वाले जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा 18 एवं 20 जुलाई को मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कैंप लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ जिससे ऐसे बचे हुए मतदाताओं को सूचीबद्ध किया जा सके। इन कैंपों पर मतदाताओं की सहायता के लिए वोलेंटियर्स, हेल्पडेस्क मैनेजर, बीएलओ सुपरवाईजर उपस्थित रहेंगे जो मतदाताओं को उनका इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने एवं उसे हाथों हाथ जमा करने में सहायता करेंगे। यदि कोई मतदाता किसी कार्य से अपने मतदान केंद्र से दूसरे स्थान पर रह रहे है, वैसी स्थिति में आप अपने मतदाता पहचान पत्र वाले मतदान केंद्र की बीएलओ से ही संपर्क करें। पदाधिकारी के. रवि कुमार बुधवार, को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर रहे थे।

पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बीएलओ द्वारा अपने मतदाताओं से संपर्क करते हुए उन तक ससमय इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं तक बीएलओ की पहुंच बेहतर है वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक मतदाताओं को जानते हैं। अतः यह कैंप केवल शहरी क्षेत्रों के लिए ही विशेष परिस्थिति में लगाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराने का कार्य जैसे कर रहे है, यथावत करेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि एएसडीडी सूची को मूर्त रूप देते समय बीएलओ एवं बीएलए-2 इस बात का ध्यान रखें कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छुटे न, एवं एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में न जुड़े। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक के लिए सभी जिलों को एएसडीडी की सूची तैयार करने के लिए प्रपत्र भेजी जा रही है। पदाधिकारी ससमय बीएलओ को उक्त विहित प्रपत्र उपलब्ध कराना एवं इसे भरने हेतु प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस प्रपत्र में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी (विदेशी) हेतु अलग अलग एनेक्सचर दिए गए हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाईजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

थार चालक ने मोरहाबादी में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले को मारी टक्कर

रांची, एजेंसी। रांची के मोरहाबादी प्राइम पार्क के पास मंगलवार (14 जुलाई) को वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल काले रंग की थार को भी जब्त कर लिया है। घटना के बाद फरार थार का वाहन नंबर ट्रेस कर संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। अभियुक्त की पहचान विश्राम उरांव (38 वर्ष) के रूप में हुई है। वह बरियातू, रांची का निवासी है। रांची पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान मोरहाबादी क्षेत्र से एक काले रंग की थार एसयूवी तेज गति और लापरवाही से चलती हुई आती दिखाई दी। गाड़ी में कंप्लीट ब्लैक फिल्म लगा हुआ था, विंडशील्ड टूटा हुआ, पीछे नंबर को मिट्टी लगा कर छिपाया हुआ था। वाहन की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने का संकेत दिया। हालांकि चालक ने वाहन रोकने के बजाय पुलिस टीम की ओर ही गाड़ी मोड़ दी और तेज रफ्तार में टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में पेट्रोलिंग गाड़ी के चालक को गंभीर चोट आई। चालक के सिर पर गंभीर चोट आई है और पांच स्टिच लगी है।

ओरमांझी में तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में छात्र की मौत, ग्रामीणों ने की सड़क जाम

ओरमांझी, एजेंसी। कुच्चू पथ स्थित बरवे रेस्क्यू सेंटर के समीप मंगलवार शाम करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार हाइवा (बीआर 02 क्यू 7536) की चपेट में आने से डहु निवासी एजाज अंसारी के पुत्र दिलसाद अंसारी (16) की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा का पीछा कर ब्लॉक चौक के पास उसे रोक लिया और चालक की पिटाई कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक दिलसाद अंसारी एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, ओरमांझी में नौवीं कक्षा का छात्र था। ग्रामीणों का आरोप है कि हाइवा चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। सड़क किनारे खड़े दिलसाद को टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर भागने लगा। इस दौरान सिलदीरी गांव के पास एक बिजली के खंभे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के विरोध में घटनास्थल बरवे रेस्क्यू सेंटर के समीप ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर ओरमांझी ब्लॉक चौक से कुच्चू जानेवाली सड़क को भी लोगों ने जाम कर दिया। वे मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और दुर्घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मनोज कुमार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण देर रात तक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटे हुए थे।

मानसून की चुनौतियों के बीच उत्पादन पर फोकस, बीसीसीएल सीएमडी ने अधिकारियों को दिया एक्शन प्लान

धनबाद, एजेंसी। मानसून के दौरान कोयला उत्पादन और आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में बस्ताकोला स्थित विकास भवन में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कंपनी के विभागाध्यक्ष, महाप्रबंधक और विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा मानसून के दौरान उत्पादन, सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में खदानों में जलभराव की आशंका से निपटने, पंपिंग व्यवस्था को दुरुस्त रखने, सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने और तय उत्पादन लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बारिश के कारण कोयला उत्पादन या डिस्पैच की रफ्तार प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सी एम डीमनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल की प्राथमिकता सुरक्षित माइनिंग के साथ-साथ बिना रुकावट प्रोडक्शन बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोयलांचल के किसी भी क्षेत्र में अवैध उत्खनन को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद सीएमडी ने बस्ताकोला जियो-सीपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसून को देखते हुए की गई तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों और परिचालन व्यवस्था का मौके पर जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

देश की ऊर्जा राजधानी बना रहेगा धनबाद

कोयला कम होने पर क्रिटिकल मिनरल्स संभालेंगे कमान

धनबाद, एजेंसी। धनबाद का भविष्य केवल कोयले तक सीमित नहीं रहेगा। देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला यह शहर आने वाले वर्षों में क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और खनिज अनुसंधान का भी राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है।

प्रभात खबर के स्थापना दिवस विशेषांक के लिए देश के दो प्रमुख खनन एवं ऊर्जा विशेषज्ञों - केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) के निदेशक प्रो। अरविंद कुमार मिश्र और आइआइटी (आइएसएम) के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एवं टेक्समिन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व पूर्व उपनिदेशक प्रो धीरज कुमार ने धनबाद के भविष्य पर अपने शोध व आकलन साझा किये हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ओर झरिया के विशाल कोयला भंडार देश की ऊर्जा सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बने रहेंगे, वहीं दूसरी ओर ओबी डंप, फ्लाई ऐश और खनन अपशिष्टों में छिपे क्रिटिकल मिनरल्स धनबाद को भारत की नयी खनिज अर्थव्यवस्था का केंद्र बना सकते हैं। यानी आने वाले समय में धनबाद की पहचान 'कोल कैपिटल' से आगे बढ़कर 'एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल कैपिटल' के रूप में स्थापित हो सकती है।

दुनिया तेजी से ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ विकल्पों का विस्तार हो रहा है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में आने वाले वर्षों तक कोयले की भूमिका कम होने वाली नहीं है। बढ़ती बिजली मांग, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार के कारण कोयला अभी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी बना रहेगा। ऐसे समय में धनबाद एक नये दौर की दहलीज पर खड़ा है। एक ओर झरिया कोलफील्ड सहित इसके विशाल कोयला भंडार वर्ष 2038 तक देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत बनाए रखेंगे, वहीं दूसरी और कोयला खनन से निकले ओवरबर्डन (ओबी), फ्लाई ऐश और अन्य खनन अपशिष्टों में छिपे क्रिटिकल मिनरल्स इसे भारत की नयी खनिज अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। यानी भविष्य का धनबाद केवल कोयले की राजधानी नहीं, बल्कि ऊर्जा और भविष्य के खनिजों की संयुक्त राजधानी बन सकता है।

धनबाद के अधिकांश कोयला क्षेत्रों में अभी भी खनन की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। वर्तमान में संचालित ओपनकास्ट परियोजनाओं में भी काफी कोयला भंडार शेष है, जबकि भविष्य में भूमिगत खनन का दायरा भी बढ़ेगा। झरिया और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल का विशाल भंडार आज भी उपलब्ध है। आधुनिक खनन तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से इन संसाधनों का अधिक सुरक्षित और अधिकतम दोहन संभव होगा। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भी धनबाद देश के सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका बनाये रखेगा। धनबाद की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर कोयला उद्योग पर आधारित है। बीसीसीएल और अन्य खनन कंपनियों के माध्यम से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जबकि परिवहन, मशीनरी, ठेका कार्य, कोयला लोडिंग, होटल, व्यापार, सुरक्षा, मरम्मत, छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर हैं। अगले एक दशक से अधिक समय तक इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

कोयला उद्योग का प्रत्येक विस्तार स्थानीय बाजार, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को नई गति देता रहेगा। देश की ऊर्जा व्यवस्था आज भी मुख्य रूप से कोयले पर आधारित है। लगभग 74 प्रतिशत बिजली का उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार अवश्य हो रहा है, लेकिन उनका उत्पादन मौसम पर निर्भर है। इसके विपरीत कोयला आधारित बिजली संयंत्र चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराते हैं। अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, डेटा सेंटर, इस्पात संयंत्र और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निर्बाध बिजली जरूरत फिलहाल सबसे विश्वसनीय रूप से कोयले से ही पूरी हो रही है। वर्तमान में देश हर वर्ष लगभग एक बिलियन टन (100 करोड़ टन) कोयले का उत्पादन कर रहा है और सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न सरकारी आकलनों के अनुसार वर्ष 2035 तक कोयला उद्योग की विकास गति बनी रहने तथा वर्ष 2038 के बाद ही इसके सामने बड़े स्तर की चुनौतियां उभरने की संभावना है। हालांकि, धनबाद का भविष्य केवल पारंपरिक कोयला खनन तक सीमित नहीं रहेगा। कोलबेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोयला गैसीफिकेशन, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र तथा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) जैसी तकनीकें इस क्षेत्र को नई पहचान देंगी। भविष्य में कोयले के साथ प्राकृतिक गैस उत्पादन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यदि रेलवे ढुलाई क्षमता बढ़ती है, आधुनिक खदानों का विकास होता है और नई तकनीकों को तेजी से अपनाया जाता है, तो धनबाद ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। धनबाद की सबसे बड़ी नयी संभावना कोयले से निकलने वाले अपशिष्टों में छिपी है। जिस ओवरबर्डन, फ्लाई ऐश और माइन टेलिंग्स को अब तक पर्यावरणीय समस्या माना जाता था, वही भविष्य में देश की सबसे मूल्यवान खनिज संपदा बन सकते हैं। यही वह परिवर्तन है, जो धनबाद को केवल कोयला राजधानी से आगे बढ़ाकर भारत का क्रिटिकल मिनरल हब बनाने की क्षमता रखता है।

भारत सरकार ने वर्ष 2024 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है। इनमें से 24 खनिजों की नीलामी शुरू हो चुकी है और वर्ष 2031 तक 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक केवल लिथियम का वैश्विक बाजार 500 करोड़ तक पहुंच सकता है।

रांची में पहली बार सजेगा डूरंड कप का मंच, 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में दिखेगा रोमांच

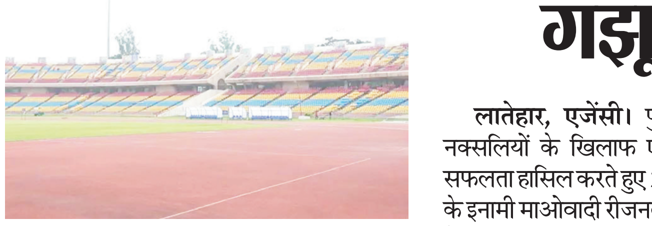

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची पहली बार देश और एशिया के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। डूरंड कप के 135वें संस्करण के तहत रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक कुल सात मुकाबले खेले जायेंगे। रांची में ग्रुप सी के सभी मैच खेले जायेंगे। इसमें छह लीग मैच के अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच शामिल है। 138 साल पुराने फुटबॉल इतिहास में यह पहली बार है, जब रांची को इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। आयोजन को लेकर राज्य के खेल विभाग, सेना और जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है।

मुकाबलों को लेकर 30 हजार की क्षमता वाले बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को एआइएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। खेल सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद स्टेडियम की पिच, फ्लड लाइट्स, खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम, दर्शकों की सुरक्षा और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

इस टूर्नामेंट के दौरान रांची के खेल प्रेमियों को भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके खिलाड़ियों को करीब से लाइव देखने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर एफसी की ओर से खेलने वाले स्टार विंगर ऋत्विक दास मैदान पर आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे, जो भारतीय सीनियर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा आइएसएल (इंडियन सुपर लीग) के बेहद अनुभवी और दिग्गज डिफेंडर प्रतीक चौधरी रक्षापंक्ति की कमान संभालेंगे।

18 पुलिसकर्मियों का 'हत्यारा' कुख्यात रवींद्र गंझू गिरफ्तार, थाने में दर्ज हैं 154 मामले

लातेहार, एजेंसी। पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20 लाख के इनामी माओवादी रीजनल कमेटी के सदस्य रवींद्र गंझू को एके-56 राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी रवींद्र, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसला बांझीटोला गांव का रहने वाला है।

रवींद्र गंझू पर 18 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ 154 नक्सली हिंसा के मामले दर्ज हैं। दरअसल, रविंद्र गंझू 16 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय था। 2019-20 तक इसका आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया था।

हालांकि पुलिस द्वारा जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लगभग नक्सलवाद का सफाया कर दिया गया तो रवींद्र गंझू काफी गोपनीय तरीके से क्षेत्र में सक्रिय था। रवींद्र गंझू एकमात्र ऐसा माओवादी कमांडर था, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। हालांकि पुलिस इसके खिलाफ लगातार छापामारी अभियान चला रही थी। इसी बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि रवींद्र गंझू अपने घर आया हुआ है।

सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई और रवींद्र गंझू के खिलाफ छापामारी की गई। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया, जब पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो रवींद्र गंझू पकड़ा गया। वहीं उसके पास से एक एके-56 राइफल, एक पिस्टल, एक राइफल, 239 गोलियां समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।

मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि कुख्यात माओवादी रवींद्र गंझू पर कुल 18 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। इसके खिलाफ लातेहार, गुमला लोहरदगा, पलामू और रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 154 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि इसके अलावा भी कई आम लोगों की हत्या का आरोप भी इस पर है। एसपी कुमार गौरव ने कहा कि गिरफ्तार माओवादी रवींद्र गंझू की पुलिस कई सालों से तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी के बाद माओवादी नक्सली संगठन का भी लगभग खात्मा हो गया है।

गिरफ्तार नक्सली रवींद्र गंझू ने पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एसपी ने आगे कहा कि जो भी नक्सली, क्षेत्र में बचे हैं, उनके पास अब एक ही विकल्प है कि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें।

महिला कांग्रेस का 21 जुलाई को 'संसद चलो' आंदोलन

महिला आरक्षण लागू करने की करेंगे मांग

झारखण्ड प्रदेश महिला कांग्रेस
प्रेस वार्ता

रांची, एजेंसी। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करेंगे। 21 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित इस आंदोलन में झारखंड सहित देश भर से महिला कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस आंदोलन को महिला कांग्रेस ने 'संसद चलो' नाम दिया है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने का दबाव डाला जाएगा।

झारखंड से दिल्ली जाने की हो रही तैयारी की जानकारी देते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस की सह प्रभारी सुधा प्रसाद ने कहा कि यह आंदोलन आक्रामक होगा और केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह लागू नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि कभी-कभी आंदोलन के क्रम में अनुशासन तोड़ना भी पड़ता है क्योंकि अब बहुत हद हो गई है। अनुशासन में रहते हुए हम लोगों ने काफी आंदोलन किया है, इसके बावजूद मोदी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

21 जुलाई को संसद चलो कार्यक्रम के तहत झारखंड के हर जिले से महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने बताया कि इस आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। झारखंड के हर जिले से महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों में टिकट भी ले लिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बार-बार झूठ बोलने का काम कर रही है और कांग्रेस पर महिला आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था लेकिन परिसीमन की आड़ में इसे लटकाने के लिए यह सोची समझी साजिश की गई और इसका दोषारोपण कांग्रेस पर मढ़ने की कोशिश की गई।

बर्थडे के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, पहले दोस्ती की फिर प्रेम जाल में फंसाया

लोहरदगा, एजेंसी। जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना का आरोप नाबालिग के प्रेमी पर लगा है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जाता है कि जिले के शहरी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसकी दोस्ती रामगढ़ जिला के चितरपुर के रहने वाले एक युवक से हुई। युवक भी उसी सेंटर में तैयारी कर रहा था। आरोपी ने पहले नाबालिग से दोस्ती की और फिर धीरे-धीरे उसे प्रेम जाल में फंसा लिया।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता की मां ने बताया कि 18 अप्रैल 2026 को आरोपी ने नाबालिग को अपने जन्मदिन के बहाने रांची स्थित अपने किराए के घर पर बुलाया। आरोपी ने नाबालिग से कहा कि उसका जन्मदिन है और उसके जन्मदिन में उसके माता-पिता और अन्य परिजन भी हैं। नाबालिग ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और वह उसके घर चली गई। जहां पर आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसे पिला दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह होने पर पीड़िता को इसकी जानकारी हुई। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। साथ ही किसी को कुछ बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद भी धमकी देकर आरोपी पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद 8 जुलाई 2026 को आरोपी लोहरदगा पहुंच गया और पीड़िता को उसके घर के बाहर से आवाज देने लगा। जब परिवार वालों ने पीड़िता से इस बारे में पूछा तो पीड़िता ने उन्हें पूरी कहानी बताई।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 25 जुलाई से, 21 से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

रांची, एजेंसी। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 25 जुलाई 2026 से होगा। परीक्षा 27 जुलाई 2026 तक रांची जिला के विभिन्न केंद्रों पर दो पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगी।

मुख्य परीक्षा में शामिल होनेवाले अभ्यर्थी 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक अपना एडमिट कार्ड व उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना पंजीयन संख्या व जन्म तिथि डाल कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाइ होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर 8929883832 पर कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 24 जुलाई तक कार्यदिवस में लिखित आवेदन देकर त्रुटि सुधार करा सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना आवश्यक होगा। परीक्षा केंद्र पर बायोमैट्रिक व आइआरआइएस की व्यवस्था की गयी है। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में सुबह आठ बजे व द्वितीय पाली में दोपहर एक बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। केंद्र पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड के साथ स्वयं का चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ व वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, किताब, खाद्य सामग्री, बैग, अस्त्र-शस्त्र आदि लाने पर प्रतिबंध है।

झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नया इतिहास,

रांची सदर अस्पताल में पहली बार हुई जटिल 'थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन' सर्जरी

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। झारखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली बार बेहद जटिल थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। धनबाद से आए एक गंभीर मरीज का यह हाई-रिस्क ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इस उपलब्धि को राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार मरीज लंबे समय से क्रॉनिक एम्पायमा से पीड़ित था। उसके फेफड़ों के आसपास मवाद और थक्के जम जाने के कारण सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिला। सर्जरी के साथ डायग्नोस्टिक थोराकोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी भी की गई।

मरीज पहले रांची के कुछ निजी अस्पतालों में भी पहुंचा था, लेकिन हृदय संबंधी अन्य बीमारियों (कार्डियक कोमोरबिडिटीज) के कारण वहां सर्जरी करने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में सदर अस्पताल की टीम ने चुनौती स्वीकार की और सफल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी देने का काम किया।

आमतौर पर बड़े निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी पर करीब 6 से 8 लाख रुपये का खर्च आता है। लेकिन सदर अस्पताल में मरीज का पूरा इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। इससे यह साबित हुआ कि सरकारी अस्पतालों में भी उच्चस्तरीय और जटिल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इस ऐतिहासिक सर्जरी का नेतृत्व सदर अस्पताल के ओंकोसर्जन डॉ। अभिनव ने किया। उनके साथ सर्जन डॉ। अखिलेश, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ। सौविक, डॉ। दीपक, डॉ। आंचल और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ। विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी टीम के समन्वित प्रयास से यह जटिल ऑपरेशन सफल हो सका।

अस्पताल प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय उपाधीक्षक डॉ। बिमलेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ। प्रभात के मार्गदर्शन और सहयोग को भी दिया है। उनका कहना है कि बेहतर टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण यह उपलब्धि संभव हो सकी।

झारखंड के सरकारी अस्पताल में पहली बार हुई यह सफल थोरैसिक डिकॉर्टिकेशन सर्जरी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल गंभीर मरीजों को राज्य में ही बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि सरकारी अस्पताल अब जटिल और हाई-रिस्क सर्जरी करने में भी सक्षम हैं।

संक्षिप्त समाचार

होटल में दूसरी महिला के साथ ठहरा था पति, पीछा कर पत्नी ने बुलाई पुलिस, दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकारपुर थाना
शिकारपुर थाना
शिकारपुर थाना
UTKARSH

बेतिया , एजेंसी। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना पुलिस ने नगर के एक होटल में छापेमारी कर एक विवाहित युवक और एक महिला को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे युवक की पत्नी की शिकायत और सतर्कता रही। पुलिस मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर, होटल संचालक से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। नरकटियागंज नगर स्थित होटल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शिकारपुर पुलिस ने अचानक छापेमारी की। पुलिस ने होटल के एक कमरे से एक युवक और एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया। दोनों की पहचान रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक विवाहित है और उसकी चार वर्ष पहले शादी हुई थी। उसकी एक छोटी बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी पिछले डेढ़ वर्ष से पारिवारिक विवाद के कारण अपनी बहन के घर नरकटियागंज में रह रही है। मंगलवार को उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ बाइक पर जाते देखा। शक होने पर वह दोनों का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई। होटल पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शन पर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उसे वहां से भगा दिया गया, इसके बाद महिला ने तुरंत शिकारपुर पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे में छापेमारी की। पुलिस के अनुसार कमरे से युवक और महिला को हिरासत में लिया गया। पत्नी का आरोप है कि उसने दोनों को होटल के कमरे में अर्धनग्न अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के कुछ होटलों में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही हैं। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस अब शहर के होटलों की नियमित जांच और सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी कर रही है।

बिहार में पानी से भरे गहरे गड्ढे में पलटी मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 महिलाओं की मौत

अररिया, एजेंसी। बिहार के अररिया से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिले के भरगामा प्रखंड स्थित सिरसिया हनुमानगंज वार्ड संख्या-14 में ब्रेक फेल होने से मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि घटना के समय ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुल 25 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर सुबह के समय धान की रोपनी करने के लिए खेत की तरफ जा रहे थे। हादसे का शिकार हुई मृतक महिलाओं की पहचान स्थानीय निवासी मीरा देवी, नैना देवी और रंजू देवी के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे सभी मजदूर ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत जा रहे थे। हनुमानगंज के पास अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर में सवार महिलाएं ट्रॉली के नीचे पूरी तरह दब गई थीं। ट्रॉली के नीचे दबने से दो महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बाकी घायलों का इलाज जारी है। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। सभी घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरगामा भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण गड्ढे में पलटा, जो बारिश के पानी से भरा हुआ था और वहां मोड़ भी है। मामले की जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि ट्रैक्टर से यह लोग खेत में धान रोपने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में यह घटना हुई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और अब तक छह से सात लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल घटना के सभी पहलूओं की जांच की जा रही है।

बिहार पुलिस सेवा के टॉप 22 अफसरों का तबादला

पटना सिटी समेत कई अनुमंडलों को मिले नए एसडीपीओ

पटना , एजेंसी। बिहार सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार पुलिस सेवा के 22 डीएसपी का स्थानांतरण कर दिया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। यह प्रशासनिक बदलाव कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

ट्रांसफर-पोस्टिंग की अधिसूचना जारी

जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतीक्षारत अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न इकाइयों में कार्यरत डीएसपी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, विशेष कार्य बल, आतंकवाद निरोधक दस्ता, अपराध अनुसंधान विभाग, यातायात शाखा और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई पुलिस ऑफिसर इधर से उधर

सरदार पटेल भवन
3
3

स्थानांतरण सूची के अनुसार अजीत कुमार बक्सर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, दानापुर (पटना) बनाया गया है। वहीं प्रेम कुमार वैशाली को एसडीपीओ, राघोपुर (वैशाली) की जिम्मेदारी मिली है। शिव शंकर कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, पटना सिटी भेजा गया है। नूलन कुमार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, हिलसा (नालंदा) तथा सहदेव दरभंगा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, बिहिया (भोजपुर) में पदस्थापित किया गया है।

राघव दयाल बने मसौढ़ी के एसडीपीओ

इसी प्रकार राघव दयाल को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, मसौढ़ी (पटना) तथा अमरनाथ को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, बिहारशरीफ (नालंदा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायचंद्र मणि त्रिपाठी को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है। वहीं आशीष राज को पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), मधेपुरा बनाया गया है। केशव कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पीरो (भोजपुर) तथा मनीष चंद्र धारिया को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सदर छपरा में तैनाती मिली है।

मिथिलेश तिवारी को पटना में एसटीएफ की जिम्मेदारी : अधिसूचना के अनुसार प्रकाश को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, सदर छपरा तथा राजू कुमार-2 को अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), बिहार पटना में भेजा गया है। इसके अलावा वर्ष 2024 बैच के सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक खालिद हयात को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई, राजन कुमार तथा मिथिलेश कुमार तिवारी को विशेष कार्य बल (एसटीएफ), बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है।

अमन महाराजगंज सीवान में ही रहेंगे तैनात

गृह विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व एक जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में क्रम संख्या-15 पर अंकित अधिकारी अमन के स्थानांतरण आदेश को स्थगित कर दिया गया है। अमन पूर्व की तरह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महाराजगंज (सीवान) के पद पर ही कार्यरत रहेंगे।

तबादले की सूची सभी अफसरों को भेजी गई

सरकार के अपर सचिव राकेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना की प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय, संबंधित जिलों के पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों का यथाशीघ्र योगदान सुनिश्चित कराते हुए आदेश का अनुपालन कराया जाए।

नेपाल में बारिश से बिहार की कोसी-गंडक, कमला नदी उफान पर

पटना, एजेंसी। बिहार के साथ ही नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक, कमला सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंगलवार को इस साल का सबसे अधिक पानी इन नदियों में रिकॉर्ड किया गया। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज के भी सभी 36 फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए और बराज से 1 लाख 75,000 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इससे वाल्मीकिनगर जंगल समेत आसपास के निचले इलाकों में पानी फैल गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी के बराहक्षेत्र में एक लाख 26 हजार क्यूसेक से अधिक पानी रिकार्ड किया गया जो इस साल का सर्वाधिक है।

गंगा-बागमती का जलस्तर बढ़ा

इधर, नेपाल में बारिश से मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिससे औराई को कटरा ब्लॉक से जोड़ने वाला कटरा पीपा पुल डूब गया। वही, पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुंगेर में भी गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कई खेतों में पानी भर चुके हैं। दियारा इलाके में कटाव हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल व्यापक स्तर पर किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए बारिश का स्वरूप स्थान-स्थान पर अलग रहेगा। कई जिलों में उमस भी बनी रहेगी और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

पंजाब सीएम भगवंत मान के बॉडीगार्ड की पत्नी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ठगे 12 लाख, बिहार से पकड़े गए 2 आरोपी

नालंदा , एजेंसी। पंजाब पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से साइबर ठगी के एक अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बॉडीगार्ड की पत्नी से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी में शामिल होने का आरोप है।

एक सप्ताह तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर ठगे 12 लाख : मामला वर्ष 2024 का है। पटियाला साइबर पुलिस को मंजीत कौर ने शिकायत दी थी कि साइबर अपराधियों ने उन्हें एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर अलग-अलग बैंक खातों में कुल 12 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की।

जामताड़ा से मिले सुराग तो नालंदा तक पहुंची जांच : जांच के दौरान गिरोह के एक सदस्य को पहले कोलकाता और झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और बरामद दस्तावेजों से पता चला कि ठगी की रकम बिहार के नालंदा जिले के दो युवकों के बैंक खातों में भी भेजी गई थी।

5 करोड़ तक की है साइबर ठगी : इसके बाद पंजाब पुलिस ने नालंदा पुलिस के सहयोग से बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसासुर निवासी मुकेश कुमार और अस्पताल चौक निवासी विशाल भारती को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह देशभर में करीब 5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। हालांकि, इस रकम की जांच अभी जारी है।

बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदले कमीशन : पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी दिल्ली स्थित एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के संपर्क में थे। गिरोह इनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम मंगाने के लिए करता था। इसके बदले दोनों को कुल राशि का करीब 2 प्रतिशत कमीशन मिलता था।

आरोपियों को पंजाब ले गई पुलिस : गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों का बिहारशरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पंजाब पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ पंजाब ले गई।

देशभर में फैला है नेटवर्क : पंजाब पुलिस के अनुसार, यह साइबर गिरोह देश के कई राज्यों में सक्रिय है। प्रारंभिक जांच में गिरोह द्वारा करीब 5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और ठगी की वास्तविक राशि व नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

साजिश के तहत फंसाया' कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह को मिली जमानत, गुंजन सिंह को भी राहत

गोपालगंज, एजेंसी। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' और मशहूर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह आज गोपालगंज सिविल कोर्ट में पेश हुए। अश्लील डांस और सरेआम हथियार लहराने से जुड़े मामले में एसीजेएम-1 की अदालत में पेश होने के बाद दोनों ने बेल बॉन्ड भरा। जिसके बाद उनको जमानत मिल गई। अनंत सिंह की पेशी को देखते हुए गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।

'साजिश के तहत फंसाया': जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पर भरोसा था। साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। अच्छा लग रहा है कि आज कोर्ट से जमानत मिल गई।

'अच्छा लग रहा है कि मुझे बेल मिल गई है। वीडियो तो मीडिया वालों ने ही वायरल कर दिया था, जबकि मैं तो वहां ता भी नहीं। जब तक मैं था। कुछ नहीं हुआ था। साजिश के तहत ऐसा किया गया। वहां तो प्रशासन भी था। कुछ गलत था तो वहां न पूछते सरासर गलत हुआ। '- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा

क्या बोले अधिवक्ता: वहीं, अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कहा, '15 जून को ही माननीय एडीजे 3 की अदालत द्वारा अनंत सिंह और गुंजन सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी। उस मामले में दोनों आज माननीय कोर्ट में बेल बांड भर कर पेश हुए। जिस वीडियो के आधार पर आरोपी बनाया गया था, वह वीडियो एडिटेड है।'

क्या है मामला: दरअसल अनंत सिंह पर आरोप है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित जनेऊ संस्कार में जब वह शामिल हुए थे, तब उस कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ। साथ ही हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में बाहुबली अनंत सिंह और गुंजन सिंह समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद दोनों आरोपियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से दोनों को 15 जून को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। वहीं, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अग्रिम जमानत मिलने के बाद आज दोनों औपचारिक रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और बेल बॉन्ड भरा।

घूसखोर सीओ गिरफ्तार, बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन

सीतामढ़ी, एजेंसी। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार को ये कार्रवाई की है। वर्ष 2025 में दर्ज एक भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक्शन हुआ है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम मंगलवार को बाजपट्टी पहुंची। टीम ने सीधे अंचलाधिकारी प्रभात कुमार के सरकारी आवास पर दस्तक दी। न्यायालय से जारी वारंट दिखाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निगरानी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई।

प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कार्य कराने के बदले अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में वर्ष 2025 में निगरानी थाना में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच की। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप: सीओ की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई। सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में इस कार्रवाई की चर्चा होने लगी। कई लोग यह जानने के लिए मौके पर पहुंचे कि आखिर निगरानी की टीम किस मामले में कार्रवाई कर रही है।

मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद,

26 साल चला केस, एक आरोपी बरी, 5 की सुनवाई के दौरान मौत

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बहुचर्चित 26 साल पुराने किसान रामबहादुर राय हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 दशरथ मिश्र की अदालत ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

खेत के विवाद में हुई थी हत्या

यह मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के झौआ गांव का है। 13 अगस्त 2000 को खेत की मेड़ काटने और धान उखाड़ने के विवाद के दौरान किसान रामबहादुर राय पर भाले से हमला किया गया था। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में लाठी, फरसा और गड़ासा से किए गए हमले में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

12 दोषियों को मिली उम्रकैद

अदालत ने भूपेंद्र प्रसाद यादव (76) और लोभित राय (78) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया। वहीं सिकिंदर राय, सत्यनारायण राय, मुनिंद्र राय, नरेश राय, रामनाथ राय, अमृत राय, विनोद राय, मोहित राय, मनोज राय और देवनारायण राय को धारा 302/149 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।

मामले में आरोपी राजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई।

फैसले के बाद कोर्ट परिसर बना अखाड़ा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुरुआत में प्राथमिकी में 11 लोगों को नामजद किया गया था। बाद में गवाहों के बयानों के आधार पर सात अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए। ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो जाने के बाद 13 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चला, जिनमें से 12 को दोषी ठहराया गया।

एफआईआर के बाद बढ़ी थी आरोपितों की संख्या : सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान मृतक पक्ष के धर्मेंद्र यादव, अरुण कुमार और विजय राय के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें धर्मेंद्र यादव घायल हो गए।

सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। परिवार ने फैसले का किया स्वागत : मृतक के भतीजे अरुण कुमार ने कहा कि ''परिवार ने करीब 26 वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया। मुकदमे के दौरान कई बार समझौते के लिए जमीन और धन का प्रलोभन दिया गया, लेकिन परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। अदालत के फैसले से हमें आखिरकार न्याय मिला।''

संक्षिप्त समाचार

घंटाघर फीडर बनाकर हिंदी बाजार का बांटा लोड, चार हजार घरों का राहत

गोरखपुर , एजेंसी। अब सराफा बाजार में बिजली फाल्ट की समस्या दूर हो जाएगी। बिजली निगम ने दो फेज में व्यवस्था सुधार का निर्णय लिया है। पहले फेज में लालडिग्गी बिजली उपकेंद्र से एक नया घंराघर फीडर बनाकर हिंदी बाजार फीडर का लोड कम कर दिया गया है। दोनों फीडरों के बीच आरएमयू (रिंग मेन यूनिट) स्थापित की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक फीडर से दूसरे फीडर को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा सकेगी। दूसरे चरण में ढीले तार कसे जाएंगे और जर्जर तारों को बदला जाएगा। बिजली निगम के अनुसार, पहले हिंदी बाजार फीडर से 19 ट्रांसफॉर्मरों पर लगभग 200 एंपियर का लोड संचालित होता था। अलग होने के बाद घंटाघर, रायगंज और बनकटी चक सहित 11 ट्रांसफॉर्मर नए घंटाघर फीडर से संचालित होंगे, जबकि गोपी गली, गहना बाजार, मदरसा चौराहा, सराय और जेके कॉम्प्लेक्स सहित 10 ट्रांसफॉर्मर हिंदी बाजार फीडर से जुड़े रहेंगे। इससे दोनों फीडरों पर लोड संतुलित होगा। उपखंड अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि इस व्यवस्था से हिंदी बाजार और घंटाघर क्षेत्र के करीब चार हजार उपभोक्ताओं को बार-बार फीडर ट्रिप होने की समस्या से काफी राहत मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय होगी। अधीक्षण अभियंता (शहरी) रणजीत चौधरी, अधिशासी अभियंता अंकित कुमार और अवर अभियंता संदीप कुमार की देखरेख में कार्य पूरा कर दोनों फीडरों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया।

स्कूल, चाय की दुकान और गुमटी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

गोरखपुर , एजेंसी। जिले में सोमवार रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने प्राथमिक विद्यालय, चाय की दुकान और पान की गुमटी को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तीनों घटनाओं में पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में आरोपियों का सुराग नहीं लग सका है। सहजनवां थाना क्षेत्र के नगर पंचायत घघसरा स्थित तुलसीदास नगर कोड़री हड़ही प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर शौचालय में लगा टुल्लू पंप, मिड-डे मील के लिए रखा 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल चोरी कर लिया। प्रधानाध्यापक शीत कुमार मंगलवार सुबह विद्यालय पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। कार्यालय में रखा इन्वर्टर भी गायब मिला, जिसे बाद में विद्यालय की बाउंड्री के बाहर अशोक के पेड़ के नीचे बोरी में बरामद कर लिया गया। प्रधानाध्यापक ने चोरी की तहरीर दी है। चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर, गोला थाना क्षेत्र के बेवरी चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान में छत के रास्ते घुसे चोर लगभग 50 हजार रुपये नकद, सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर चोरी कर ले गए। दुकान मालिक प्रभुनाथ ने बताया कि सोमवार सुबह दुकान खोलने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं, पिपराइच थाना क्षेत्र के कोनी तिराहे पर चोरों ने पान की गुमटी का ताला तोड़कर करीब एक लाख रुपये का सामान चुरा लिया। पीड़ित राधेश्याम जायसवाल के अनुसार गुमटी से सामान गायब मिला। सूचना पर डायल- 112 और पिपराइच पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

नशे में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर को जांच के बाद हटाया

मेरठ , एजेंसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ड्यूटी के दौरान विवाद के बाद चिकित्सक दीपक कुमार को सीएमओ ने हटा दिया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष आदेश कसाना की तबीयत इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ने और चिकित्सक पर नशे की हालत में ड्यूटी करने के आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई हुई। मामले की जांच डिप्टी सीएमओ को सौंपी गई थी। 25 जून की शाम आदेश कसाना को पेट दर्द की शिकायत पर सीएचसी सरूरपुर ले जाया गया। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक दीपक कुमार ने उन्हें दो इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि चिकित्सक नशे की हालत में अभद्र व्यवहार कर रहा था। घटना की जानकारी सीएमओ को दी गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक का मेडिकल परीक्षण कराकर कार्रवाई की मांग की और तहरीर भी दी। चिकित्सक ने पारिवारिक परेशानी के चलते नशा करने की बात स्वीकार की थी। कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक को सीएचसी से हटाने की मांग करते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। इस मामले की जांच डिप्टी सीएमओ कांति प्रसाद को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमओ रामप्रसाद ने दीपक कुमार को सीएचसी सरूरपुर से हटाने के आदेश जारी किए। सीएचसी प्रभारी राघो सिंह को चिकित्सक को हटाए जाने की मौखिक सूचना मिली है, हालांकि लिखित आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

48 महीने और छह अर्थियां, एक-एक कर पिता-पांच बेटों की मौत

अब भरण-पोषण को भी मोहताज

भी रो पड़ेंगे!
कुल छह मौते

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकटिया गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लोग भगवान से भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि भगवान आखिर किसी परिवार से इतना रुष्ठ कैसे हो सकते हैं। यहां मात्र चार वर्ष के भीतर लगातार छह मौतें हुई हैं। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है।

29 सितंबर 2022 की वो तारीख इस घर के लिए कयामत बनकर आई। उस दिन प्रेम कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय किशन कुमार गुप्ता की मौत हुई और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ, जो चार साल में पूरे परिवार को उजाड़ गया। इसके बाद 17 नवंबर 2023 को सुधीर गुप्ता कानपुर में किराये के मकान में आग लगने से संदिग्ध हालात में चल बसे।

एक-एक कर पांच बेटों और पिता की मौत

10 अक्टूबर 2023 को किशन कुमार गुप्ता ने दुनिया को अलविदा कहा। 24 अक्टूबर 2024 को सोहन गुप्ता ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। फिर एक जुलाई 2026 को छोटू और 10 जुलाई को मोहन गुप्ता भी नहीं रहे। बीमारी और संदिग्ध हालातों ने एक-एक कर पांच बेटों और पिता को निगल लिया।

न सिर्फ रिश्ते छीने, घर की कमर भी तोड़ दी

हरे-भरे आंगन में कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सिसकियों की आवाज है। मां रामजानकी की गोद सूनी हो गई है, अब घर में सिर्फ बड़ा बेटा शंकर, छोटी बेटी खुशी और बूढ़ी मां बची हैं। रो-रोकर तीनों का बुरा हाल है। लगातार मौतों ने न सिर्फ रिश्ते छीने, बल्कि घर की कमर भी तोड़ दी है।

अर्थी उठाने के लिए भी मोहताज होना पड़ा

आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि 10 जुलाई को मोहन गुप्ता के अंतिम संस्कार का सामान तक घर में नहीं था। पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर अर्थी सजाई और दाह संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। जिस घर में कभी शादियों के ढोल बजते थे, वहां अब अर्थी उठाने के लिए भी मोहताज होना पड़ा। गांव वाले कहते हैं कि भगवान आखिर इतना कैसे रूठ सकता है।

सवाल- टूटे परिवार को अब कौन सहारा देगा

चार साल में एक पिता और पांच बेटे चले गए। घर पर अब खाने के लाले हैं। कमाने वाला कोई नहीं बचा। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने राजस्व विभाग से मदद की गुहार लगाई है। एक साथ छह मौतों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। हर आंख नम है और हर जुबान पर यही सवाल है कि इस टूटे परिवार को अब कौन सहारा देगा। डीडीओ आत्म प्रकाश रस्तोगी ने बताया कि इस तरह के मामलों में राजस्व विभाग की तरफ से पारिवारिक लाभ दिया जा सकता है। इसके साथ ही मृतकों की मां को विधवा पेंशन दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ सहयोग हो सकता है, तो जांच कर कराई जाएगी।

मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा में गोरखपुर प्रदेश में अव्वल

गोरखपुर , एजेंसी। गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में गोरखपुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जून की रैंकिंग में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) सेवा के संचालन में गोरखपुर को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले में संचालित पांच मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, दवाएं और लैब जांच की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले की पांचों मोबाइल मेडिकल यूनिट उन गांवों में नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं, जहां जिला अस्पताल, सीएचसी या पीएचसी की पहुंच सीमित है। प्रत्येक यूनिट में एक चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट तैनात हैं।

जून में पांचों यूनिटों के माध्यम से जिले के विभिन्न गांवों में 50 ओपीडी आयोजित की गईं। इनमें 7,053 मरीजों का चिकित्सकीय परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गईं। वहीं 1,965 मरीजों की मौके पर ही पैथोलॉजी जांच की गई। जांच के दौरान गंभीर बीमारी के लक्षण मिलने पर मरीजों को जिला अस्पताल और उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया।

सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के प्रभावी संचालन के कारण गोरखपुर को जून माह में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और शासन की प्राथमिकता का परिणाम है। इससे ग्रामीणों को घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

सीएम डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, गोरखपुर मंडल के अन्य जिले महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर ने भी जून माह में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ए ग्रेड हासिल किया है। इन जिलों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शत-प्रतिशत क्रियाशीलता दर्ज की गई।

कचरे में नहीं जाएगी राखी, मिट्टी में जाते ही बनेगी पौधा

अलीगढ़ , एजेंसी। अतरौली के गांव खेड़ाबाद नगलिया की महिलाएं भाई-बहन के प्रेम के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं। गांव की अलका वर्मा के नेतृत्व में जय शनि देव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस बार ऐसी सीड राखी (बीज वाली राखी) तैयार की है, जो बाद कचरे में नहीं जाएगी, बल्कि मिट्टी में जाते ही कुछ समय बाद पौधे का रूप ले लेगी।

समूह संचालिका अलका वर्मा ने बताया कि सामान्य राखियां त्योहार के बाद कचरे में चली जाती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसी समस्या को देखते हुए महिलाओं ने पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाने का निर्णय लिया। इन राखियों को तैयार करने में मिट्टी, हैंडमेड पेपर और सूती-रेशमी कलावे का प्रयोग किया गया है।

इन विशेष राखियों में तुलसी, गेंदा, टमाटर और मिर्च जैसे उपयोगी एवं औषधीय पौधों के बीज लगाए गए हैं। रक्षाबंधन के बाद भाई इन राखियों को गमले या बगीचे की मिट्टी में लगा सकते हैं, जहां कुछ समय बाद पौधे विकसित हो जाएंगे।

अलका वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मेहनत से इन राखियों को तैयार कर रही हैं और बाजार में भी इनकी मांग भी बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल राखियों को अपनाने से रक्षाबंधन का त्योहार रिश्तों की मिठास के साथ प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देगा। जय शनि देव स्वयं सहायता समूह की यह पहल महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सरोकार का प्रेरणादायक उदाहरण बन रही है।

प्रसव के बाद पेट में ही छोड़ दी रूई ऑपरेशन का खर्च न देने पर हंगामा

अलीगढ़ , एजेंसी। कृष्णा नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान एक महिला के पेट में रूई छूट गई। तबीयत बिगड़ने पर जब सीटी स्कैन कराया तो इसका पता चला। वादे के मुताबिक ऑपरेशन के रुपये नहीं मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया।

दरअसल, नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने दूसरी जगह ऑपरेशन कराकर कॉटन निकलवाने और सारा खर्चा देने का वादा किया था। चंडौली बुजुर्ग निवासी अरविंद चौहान ने बताया कि आठ महीने पहले गांव के ही निरंजन ने उनकी बेटी जागृति की कृष्णा नर्सिंग होम में सामान्य प्रसव कराने की बात कही थी।

अस्पताल में 40 हजार रुपये जमा कराने के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पेट के अंदर ही कॉटन छोड़ दी। प्रसव के बाद से ही जागृति को लगातार पेट में गंभीर दर्द रहने लगा। अस्पताल के लोग हर बार दवा देकर टालते रहे। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने सीटी स्कैन कराया। इसमें पेट के अंदर रूई होने की पुष्टि हुई। पीड़िता की बहन प्रियंका ने बताया कि इस गंभीर लापरवाही के कारण जागृति का वजन घटकर महज 20 किलो रह गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने नर्सिंग होम प्रबंधन को यह बात बताई, तो बदनामी के डर से डॉक्टर ने कहा, मामला उछालो मत। दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन करा लो, सारा खर्च मैं दूंगा।

डॉक्टर के भरोसे पर परिजनों ने महिला का दोबारा ऑपरेशन कराया, जिसमें करीब 3.20 लाख रुपये का खर्च आया। जब पीड़िता के परिजन बिल का भुगतान मांगने कृष्णा नर्सिंग होम पहुंचे, तो संचालक ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और उन्हें पहचानने तक से इन्कार कर दिया।

मंगलवार को नर्सिंग होम संचालक की वादाखिलाफी से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और स्टाफ के साथ तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे को बढ़ता देख आरोपी डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को शांत कराया। पीड़िता के पिता अरविंद चौहान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार को सौंपी है।

नाले पर और किनारे बनीं 12 दुकानों को नोटिस

आगरा, एजेंसी। सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी दुकान के ढह जाने से महिला गंगादेवी की मृत्यु के बाद नगर निगम ने 12 दुकानों को नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकांश नाले के ऊपर बनी हैं और कुछ नाले के किनारे बनी हैं। इनके जर्जर होने और कभी भी ढह जाने की आशंका पर नगर निगम ने तीन दिन के अंदर दुकानें खाली कर हटाने के निर्देश दिए हैं।

इस पर व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मिलकर नोटिस पर ही सवाल उठाए और कहा कि नाले पर वह नगर निगम से आवंटन के बाद दुकानों पर बैठे हैं। अगले साल 2027 तक का संपत्ति कर भी जमा है।

जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार में नाले पर और किनारे बनीं 12 दुकानों को तीन दिन में हटाने का नोटिस नगर निगम ने जैसे ही व्यापारियों को दिया, मामला गरमा गया। व्यापारियों ने नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से मुलाकात कर कहा कि नाले पर बनी दुकानों से नगर निगम किराया वसूल रहा है, फिर यह अवैध कैसे हुई। आगरा व्यापार मंडल के जय पुरसनानी ने कहा कि 9 दुकानें सुभाष बाजार में नाले पर 1977 में बनाई गई थीं। निगम ने आवंटन किया। 9 जून को जर्जर होने पर मरम्मत के लिए दुकानदारों ने ज्ञापन दिया। जब निगम ने कार्रवाई नहीं की तो दुकान गिर गई। इसके लिए निगम दोषी है, न कि दुकानदार। दुकानों को अवैध बताना बंद कीजिए।

नोटिस में नगर निगम ने यह लिखा

मंटोला नाले के ऊपर सीसी स्लैब डालकर नगर निगम ने इसे पाटा और दुकानें बना दीं। हादसा हुआ तो अब नोटिस जारी किए गए हैं। अधिशासी अभियंता की ओर से दिए गए नोटिस में लिखा है कि नाले के सहारे होने के कारण अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। नाला 60-70 साल पुराना बना हुआ है, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। नाले के सहारे अवैध कब्जा कर आपके द्वारा दुकान बनाई गई है, जो क्षतिग्रस्त हो सकती है। और उसे तुरंत हटाने की चेतावनी दी गई है। तीन दिन के अंदर दस्तावेज मांगे गए हैं।

दरोगा के घर चोरी करने के चार आरोपी गिरफ्तार, चोरी के जेवर बरामद

लखनऊ, एजेंसी। तेलीबाग। पीजीआई क्षेत्र के हैवतमऊ मवैया में मलिहाबाद थाने में तैनात दरोगा संजय यादव के घर हुई 35 लाख रुपये के जेवरों की चोरी का पुलिस ने चार दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए करीब 80 प्रतिशत जेवर बरामद किए हैं।

इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दरोगा की पत्नी कविता यादव ने चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। परिवार 8 जुलाई को विंध्याचल दर्शन के लिए गया था। 10 जुलाई को लौटने पर घर के कमरों के ताले टूटे मिले और अलमारी में रखे करीब 35 लाख रुपये के जेवर गायब थे।आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर संदिग्धों की पहचान हुई। इसके आधार पर पुलिस ने मंगलवार को कालिंदी पार्क के पास से पिपरौली निवासी अर्जुन रावत, मोहनलालगंज मऊ निवासी सुदैफ अली, पीजीआई हैवतमऊ मवैया निवासी विजय कुमार और दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में दो अन्य साथियों के शामिल होने की बात भी कबूल की है, जिनकी तलाश जारी है। इंस्पेक्टर के अनुसार, अर्जुन के खिलाफ पहले से चार, सुदैफ के खिलाफ तीन, विनय के खिलाफ दो और दीपक के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

क्वान की-डो कार्यशाला में 18 जिलों के 44 रेफरियों ने सीखीं खेल की बारीकियां

वाराणसी , एजेंसी। उत्तर प्रदेश क्वान की-डो एसोसिएशन की ओर से आयोजित तीन दिवसीय प्रादेशिक क्वान की डो रेफरी सेमिनार और ग्रेडिंग कार्यशाला बाबतपुर के गणेशपुर में मंगलवार को संपन्न हुई। इसमें प्रदेश के 18 जिलों के 44 चयनित रेफरियों ने तीन दिनों में 27 घंटे खेल के नए नियम और रेगुलेशन की जानकारी ली। इसमें क्वान की-डो खेल के नवीनतम तकनीकी मानकों, प्रतियोगिता संचालन, नियम और विनियम का प्रशिक्षण देश के वरिष्ठ क्वान की-डो प्रशिक्षकों ने दिया।

सेमिनार में मेजबान वाराणसी के अतिरिक्त गाजीपुर, इटावा, गोरखपुर, मैनपुरी, इटावा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बहराइच, गोंडा, मथुरा, कानपुर, चंदौली, गौतम बुद्धनगर, सहारनपुर, सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रेफरियों ने सहभागिता की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रतिभागियों की प्रायोगिक, सैद्धांतिक मौखिक परीक्षाएं आयोजित की गईं। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले रेफरियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के तकनीकी निदेशक भुवनेश कुमार शर्मा और रेफरी अध्यक्ष अब्दुल मलिक खान ने तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल में दोनों टीमों का ध्यान खेल पर होता है और खिलाड़ी हर तरकीब अपनाते हैं इसी समय रेफरी का काम शुरू होता है। वह तय नियमों के आधार पर खेल सर्वमान्य तरीके से संपन्न कराता है। अंतिम सत्र का शुभारंभ उत्तर प्रदेश क्वान की-डो एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. राजकुमार सिंह गौतम ने किया। मुख्य अतिथि एसोसिएशन के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य अमित पांडेय ने सभी सफल प्रतिभागियों को ग्रेडिंग और रेफरी प्रमाण-पत्र प्रदान दिया। मौके पर संघ के सचिव उमेश केसरी, संयुक्त सचिव, सुल्तान खान, अमन कुमार, पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह मौजूद रहे।

घने बाजारों में जाम से निजात को बनेंगे 10 नए पार्किंग स्थल

आगरा, एजेंसी। घने बाजारों में व्यापारियों और जनता को जल्द ही पार्किंग की किल्लत और जाम से छुटकारा मिलेगा। जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को 10 प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया है। जमीन चिह्नित होने के बाद अब संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम और संपत्ति अधिकारी वैभव यादव ने जय पुरसनानी के साथ इन स्थलों का जायजा लिया। टीम ने जामा मस्जिद के सामने रेलवे लाइन के पास, नाला महावीर, बिजलीघर स्थित रक्षा विभाग की जमीन, पीपल मंडी, पुरानी चुंगी दरेसी नंबर-3, हाथी घाट स्थित शौचालय के पीछे, शाहगंज विद्यालय के पास, सिंधी बाजार और कोतवाली के समीप के स्थलों को परखा। सिंधी बाजार में जलकल टंकी पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है, जबकि पीपल मंडी में पुरानी पार्किंग के ऊपर नई पार्किंग बनाई जाएगी। निरीक्षण के बाद नगर निगम अब इन जमीनों पर अपनी सहमति बनाएगा।

तीन दिन से तलाश, बंद मोबाइल और फिर नाले में मिला शव

आगरा, एजेंसी। आगरा के थाना एकता की पंचवटी कॉलोनी में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करने वाले 50 वर्षीय अब्दुल कलाम 11 जुलाई से लापता थे। मंगलवार को परिजनों ने सीसीटीवी देखने के बाद कॉलोनी के पास नाले में तलाश की तो उनका शव नाले में मिला। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। नगला मेवाती निवासी आलिया ने बताया कि उनके पिता अब्दुल कलाम तीन वर्षों से पंचवटी कॉलोनी सुरक्षाकर्मी की नौकरी करते थे। 11 जुलाई को सुबह 11 बजे वह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। शाम 7 बजे कॉलोनी से निकले थे पर घर नहीं पहुंचे। मोबाइल भी बंद जा रहा था। कॉलोनी जाकर उनके मैनेजर से बात की पर उसने कोई सहयोग नहीं किया और जानकारी न होने की बोलकर पल्ला झाड़ दिया। काफी कहने पर भी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई।

इस पर उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी का प्रार्थनापत्र दिया। मंगलवार को वह मां बिलकिश और अन्य परिजन के साथ कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनीवासियों के कहने पर रिकॉर्डिंग दिखाई गई। रिकॉर्डिंग में 11 जुलाई की शाम 7 बजे पिता सड़क पार करते हुए दिखे। इसके बाद सड़क किनारे नाले में जाकर देखा तो थोड़ी दूर पर नाले में पिता का शव दिख गया। अब्दुल कलाम के परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा। प्रथम दृष्ट्या मामला हादसा लग रहा है।

सक्षिप्त समाचार

जज विनय सिंघल के खिलाफ शुरू होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (डीएचजेएस) के न्यायिक अधिकारी विनय सिंघल को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने तक तत्काल प्रभाव से निंलबित कर दिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा 10 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि विनय सिंघल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि निलंबन की अवधि के दौरान व तीस हजारी कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) में संबद्ध रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगें।

वंदे भारत बनी पहली पसंद, यात्रियों की संख्या में 83% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। रेल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि अधिकांश रूट की ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी होती है। मेल एक्सप्रेस के साथ ही वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों जिनमें अधिक किराया लगता है में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अप्रैल-जून 2026 के दौरान उत्तर रेलवे से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में 1,47,462 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 80,394 थी। इस प्रकार यात्री संख्या में 83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वंदे भारत ट्रेनों से प्राप्त आय 7.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.21 करोड़ हो गई, जो 72 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस अवधि प्रारंभिक यात्रियों की संख्या यानी ट्रेन जहां से शुरू होती है वहां से यात्रा करने वालों की संख्या 11.43 करोड़ से बढ़कर 12.07 करोड़ हो गई, जो 5.6 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, प्रारंभिक यात्री आय 3,083.42 करोड़ से बढ़कर 3,567.59 करोड़ हो गई, जो 15.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि इन उपलब्धियों के पीछे केंद्रित परिचालन रणनीति, संसाधनों का बेहतर उपयोग, सतत निगरानी, प्रभावी टिकट जांच व्यवस्था, क्षेत्रीय स्तर पर सुदृढ़ पर्यवेक्षण तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामूहिक प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर रेलवे भविष्य में भी यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, परिचालन उत्कृष्टता बनाए रखने तथा रेलवे के राजस्व में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इसी समर्पण के साथ कार्य करता रहेगा।

दिल्ली पुलिस के 'ऑपरेशन विश्वास' से खिले चेहरे

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य जिला पुलिस ने जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के साथ ही आपरेशन विश्वास के तहत 30 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। शनिवार को जिले के सभी थानों में आयोजित जन सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सीधे सुनीं और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, पिछले 30 दिनों में सीईआइआर पोर्टल पर दर्ज खोए मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण, लगातार फालोअप और फील्ड टीमों के समन्वित प्रयासों से पता लगाकर बरामद किया गया। सत्यापन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आपरेशन विश्वास तकनीक आधारित प्रभावी पुलिसिंग का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा और पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत करना है।

मतदाता सत्यापन की दौड़ से सीएससी और इंटरनेट कैफे पर 100% तक बढ़ा काम, देर रात तक जुटे ऑपरेटर

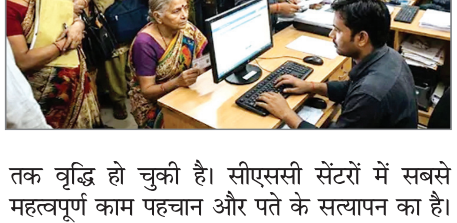

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में एसआइआर की सरगर्मियां तेज हैं। हर आयु वर्ग मतदाता जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हुए हैं। उसका सीधा असर दिल्ली के कामन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) और गली- मोहल्लों में चलने वाले इंटरनेट कैफे पर नजर आ रहा है, जहां संचालकों तथा उसके कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ गया है।

दिल्ली में 7,000 सीएससी सेंटर हैं। इसके साथ ही 10 हजार से अधिक कैफे संचालक है। जिनके यहां एसआइआर के चलते 100 प्रतिशत तक काम में वृद्धि हुई है।

दस्तावेजों को दुरुस्त करने और समय पर आवेदन करने के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित सीएससी और कैफे देर रात तक खुले रह रहे हैं। दिनभर काम- काज में व्यस्त रहने वाले लोग रात के समय इन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। आपरेटर भी बढ़ी हुई मांग को देखते हुए अतिरिक्त घंटों तक काम कर रहे हैं, जिसके लिए लोग निर्धारित शुल्क भी चुका रहे हैं। एक सीएससी के संचालक सत्येंद्र कुमार के अनुसार, लोग देर रात तक आ रहे हैं। उन्होंने अलग से तकनीक विशेषज्ञ रखे हैं। काम में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। सीएससी सेंटरों में सबसे महत्वपूर्ण काम पहचान और पते के सत्यापन का है। लोग सीएससी सेंटर में पहुंच कर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजने, उसे डाउनलोड करने और प्रिंट निकलवाने का काम अधिक करवा रहे है।

इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए लोग खुद फार्म भरने के बजाय इन सेंटर्स के आपरेटरों पर भरोसा कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में एसआइआर की इस दौड़ ने स्थानीय स्तर पर सीएससी और छोटे कैफे संचालकों का काम बढ़ा दिया है।

98 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को बंटा फार्म वैसे, एसआइआर में भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनाव कार्यालय द्वारा सोमवार को देर शाम तक दिल्ली के कुल मतदाताओं 1,45,10,298 में से 14,30,2626 मतदाताओं को एसआइआर संबंधित फार्म वितरित किए गए।

इस तरह अब तक कुल 98.57 प्रतिशत मतदाताओं को फार्म बांट दिए गए हैं। जिसमें से 17,66,553 यानि 12.17 प्रतिशत मतदाताओं का आनलाइन सत्यापन भी हो गया है।

सिर्फ पद के आधार पर अस्पताल निदेशक पर नहीं चल सकता मुकदमा, व्यक्तिगत भूमिका के साक्ष्य जरूरी : कोर्ट

नईदिल्ली, एजेंसी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी अस्पताल के निदेशक को केवल उसके पद के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निदेशक के खिलाफ आपराधिक दायित्व तय करने के लिए उसकी व्यक्तिगत भूमिका और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य होना अनिवार्य है। मामला पूर्वी दिल्ली स्थित तनेजा अस्पताल में भर्ती अल्लाह रखी नामक महिला की मौत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि महिला को जबरन अस्पताल में भर्ती किया गया और पूर्व नियोजित साजिश के तहत ऐसा इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत में अस्पताल प्रबंधन पर उपचार संबंधी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और बिना वैध सहमति के इलाज करने के आरोप भी लगाए गए थे। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2025 में अस्पताल से जुड़े दो कॉरपोरेट निदेशकों को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में तलब किया था। इसके खिलाफ दोनों निदेशकों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। शिकायत, पुलिस जांच और उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित हो कि दोनों निदेशकों की मरीज के इलाज, चिकित्सकीय निर्णय या कथित लापरवाही में कोई प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत भूमिका थी।

गांधी की लाठी से सेंगोल तक...

पीएम संग्रहालय की 'वॉकिंग विद लेगेसी' प्रदर्शनी में सजी विरासत

नई दिल्ली, एजेंसी। ये महज लकड़ी की छड़िया नहीं है जनाब... बल्कि विरासत और हस्तशिल्प की उत्कृष्ट गाथा है। यह अद्भुत और विशिष्ट लकड़ी के डंडे इतिहास बदलने वालों के हाथ में सुशोभित रहे। उनके सफर का सहारा रहे तो उनके व्यक्तित्व की मुकम्मल पहचान भी बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लाठी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर थामे गए सेंगोल तक, एक ऐसी विरासत, जो सादगी के साथ भव्यता तथा उत्कृष्ट व दुर्लभ कारीगरी की अद्भुत यात्रा कराती है। चाणक्यपुरी स्थितप्रधानमंत्री संग्रहालय के ब्लाक-एक स्थित परिचय गैलरी में इन दिनों विशेष प्रदर्शनी ' 'वाकिंग विद लेगेसी'' (विरासत के साथ कदम) की शुरुआत हुई है, जो आम दर्शकों के लिए 24 जुलाई तक खुली रहेगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संग्रहालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डा. प्रियंका मिश्रा भी मौजूद रहीं। इस प्रदर्शनी में संग्रहालय के तोशाखाने से चुनी गई ऐतिहासिक 31 छड़ियों और बैटन को प्रदर्शित किया गया है, जो पहचान और शासन का प्रतीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा समय-समय पर इस्तेमाल की गई थी या उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उसमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में उन्हें सौंपा गया था। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई यह समृद्ध परंपरा नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक आया और उसे उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर थामा। इसी तरह, आरक्षित संग्रह से संविधान निर्माता भीम राव आंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों व राजनेताओं के हाथ की शोभा रही छड़ियों को प्रदर्शित किया गया है।

अंकित शर्मा हत्याकांडः अदालत के लिए आसान नहीं था फैसला

सबूतों की पड़ताल को घटनास्थल तक पहुंची थी कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान आइबी कर्मी अंकित शर्मा हत्याकांड में गवाहों और सुबूतों के बीच उलझी गुत्थी को सुलझाना अदालत के लिए आसान नहीं था। वकीलों की जिरह के बीच पेच फंसा तो न्याय की कसौटी पर सुबूतों और गवाहों को कसने के लिए अदालत ने खुद उस स्थान पर पहुंची, जहां आइबी कर्मी की हत्या की गई थी। यहां अदालत के सामने ही दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीन-रीक्रिएशन किया गया, ताकि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के दावों की हकीकत को धरातल पर जांचा जा सके। कानून के जानकारों की मानें तो न्याय प्रक्रिया के इतिहास में शायद यह पहली घटना है, जिसमें सुबूतों और गवाहों की सच्चाई जानने के लिए कोर्ट खुद घटनास्थल पर पहुंची।

विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडेय ने विशेष बातचीत में बताया कि केस की सुनवाई के दौरान कई मोड़ आए। पहला मोड़ तब आया जब अंकित के पिता रविंदर शर्मा ने कोर्ट में कहा कि एफआइआर पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं।

वह हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, जबकि एफआइआर में अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं। अंकित के पिता के बयान को बचाव पक्ष ने उनके खिलाफ ही प्रयोग किया। हालांकि, उन्हें इसका ज्यादा लाभ नहीं मिला।

उन्होंने बताया कि अदालत के सामने असमंजस की स्थिति तब पैदा हुई, जब गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने संदेह पैदा करने का काम किया। बचाव पक्ष ने कहा कि चांदबाग पुलिया सड़क से काफी ऊंची है, ऐसे में गवाह जहां खड़े थे। वहां से ताहिर व अन्य आरोपितों को देख ही नहीं सकते।

अब आधुनिक तकनीक के साथ नए युग में प्रवेश कर रही है

आचार्य सुश्रुत से रोबोटिक सर्जरी तकः आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का नया अध्याय, दुनिया में बढ़ी भारत की पहचान

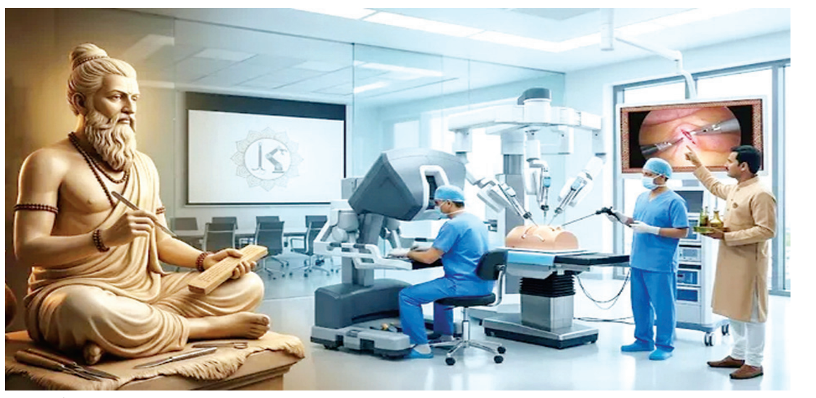

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व में शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले आचार्य सुश्रुत की 2,500 वर्ष पुरानी विरासत अब आधुनिक तकनीक के साथ नए युग में प्रवेश कर रही है। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा अब केवल पारंपरिक शस्त्रकर्म तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक, माइक्रोवैस्कुलर और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के समावेश से उपचार की नई दिशा तय कर रही है।

प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह संगम न केवल मरीजों के लिए अधिक सटीक, सुरक्षित और समग्र उपचार का मार्ग खोल रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की स्वीकार्यता को भी तेजी से बढ़ा रहा है।

आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में अष्टविध शस्त्रकर्म, व्रण प्रबंधन, अग्निकर्म, क्षारकर्म, रक्तमोक्षण और मर्म चिकित्सा का विस्तृत वैज्ञानिक वर्णन किया था। नाक के पुनर्निर्माण (राइनोप्लास्टी) की उनकी तकनीक को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की आधारशिला माना जाता है।

यही कारण है कि विश्व चिकित्सा जगत आज भी आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक स्वीकार करता है। इन्हीं सिद्धांतों को आधुनिक सर्जिकल तकनीकों के साथ जोड़कर आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। इस एकीकृत माडल के तहत डायबिटिक अल्सर और जटिल घावों के उपचार में आयुर्वेदिक व्रण चिकित्सा के साथ आधुनिक ड्रेसिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

इलाज की गुणवत्ता में होगा सुधार

फिस्टुला और बवासीर जैसी बीमारियों में क्षारसूत्र पद्धति के बेहतर परिणाम पहले से स्थापित हैं। अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा को पुराने दर्द एवं मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में आधुनिक उपचार के साथ अपनाया जा रहा है।

रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में सुश्रुत की फ्लैप तकनीकों को आधुनिक माइक्रोसर्जरी से जोड़ा जा रहा है, जबकि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तकनीकों के साथ आयुर्वेदिक प्री एवं पोस्ट-आपरेटिव देखभाल के समन्वय पर भी तेजी से काम हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मरीजों की रिकवरी बेहतर होने और उपचार की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है।

राष्ट्रपति आज करेंगी 'सौश्रुतम्-2026' का शुभारंभ

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआइआइए) में 15 से 17 जुलाई तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'सौश्रुतम्-2026' का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी। सम्मेलन में आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव, दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत सहित थाईलैंड, इजराइल, ब्रिटेन, श्रीलंका समेत कई देशों के शल्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें रोबोटिक सर्जरी का लाइव प्रदर्शन, वैज्ञानिक सत्र, शोध पत्र प्रस्तुतियां और पैनल चर्चाएं होंगी।

ईरान बातचीत करे नहीं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे', ट्रंप की धमकी- जल्द पावर प्लांट और पुलों पर करेंगे हमले

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटा तो अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तेहरान, वॉशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि अगर वार्ता दोबारा शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करेगा।

ट्रंप ने कहा, 'हम कल रात उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। उसके अगले दिन भी कड़ा हमला करेंगे और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों की बारी आएगी। अगर वे बातचीत की मेज पर आकर बातचीत नहीं करते तो अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी। हम उनके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को तबाह कर देंगे।'

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच संपर्क बना हुआ है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर समुद्री यातायात पर प्रतिबंध जारी रखेगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।

ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक जारी रहेगा? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक वह उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में जमीनी सेना भेजने की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि वह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, 'कभी-कभी जमीनी अभियान की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी ओर से जमीनी अभियान चलाएंगे।' ट्रंप ने तेहरान पर समझौते का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि यदि ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, 'बेहतर होगा कि आप समझौता कर लें। नहीं तो आपके पास कोई नहीं बचेगा।'

ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका नागरिकों के हताहत होने की आशंका को कम करने के लिए ज्यादा सावधानी बरत रहा है। उन्होंने कहा, 'हम नागरिक आबादी को लेकर बेहद सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि बेहतर होगा आप (ईरान) समझौता कर लें। नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा।'

बड़ी संख्या में भारतीय थाइलैंड घूमने के लिए जाते हैं

थाइलैंड में भारतीयों के लिए बिना वीजा के एंट्री जारी, लेकिन एक शर्त

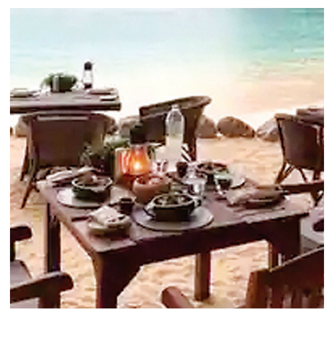

बैंकाक, एजेंसी। थाइलैंड में भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा एंट्री मिलती रहेगी। हालांकि इसमें एक बदलाव भी किया गया है। बिना वीजा के भारतीय थाइलैंड में अधिकतम 30 दिन तक ही रुक पाएंगे। यह वजह, थाई सरकार ने एक खास वजह से लिया है। असल में भारतीयों के वीजा-फ्री एंट्री पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव के बाद से भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। बता दें कि थाइलैंड के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। बड़ी संख्या में भारतीय थाइलैंड घूमने के लिए जाते हैं। थाइलैंड कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में भारतीय यात्रियों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी। पर्यटन मंत्री सुरसक पंचरोएनवोराकुल ने कहाकि इस कदम का उद्देश्य भारतीय पर्यटकों के लिए चीजों को आसान करना है। इससे देश के पर्यटन उद्योग को भी सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने कहाकि इसलिए कैबिनेट ने भारतीय पर्यटकों के लिहाज से 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी। यह थाइलैंड के लिए एक बड़ा बाजार हैं। साथ ही पर्यटन मंत्री ने यह भी कहाकि अगर भविष्य में इस कदम से कोई समस्या आती है, तो सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है। भारतीय यात्रियों को फिलहाल बिना वीजा के थाइलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति है। लेकिन मई में थाई कैबिनेट द्वारा वीजा-मुक्त देशों की सूची को 93 से घटाकर 54 करने और 30 दिन की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह पॉलिसी खत्म होने वाली थी। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुआ है। पर्यटन मंत्री के अनुसार, इस घोषणा ने भारतीय यात्रियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया और यहां से थाइलैंड आने वालों की संख्या काफी कम हो गई। भारत इस साल चीन और मलेशिया के बाद थाईलैंड के लिए तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स है।

भारत के साथ-साथ, थाइलैंड ने क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के यात्रियों के लिए भी 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी है। यह जानकारी डिप्टी सरकारी प्रवक्ता प्लॉयटाले लक्समीसांगचन ने दी। इस नए फैसले के बाद 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री के लिए योग्य देशों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसमें सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी शामिल हैं। प्लॉयटाले ने कहा कि अपडेट की गई नीति थाई पासपोर्ट धारकों के लिए शेंगेन वीजा छूट हासिल करने के थाई प्रयासों को भी समर्थन दे सकती है। वीजा नीति में बदलाव ऐसे समय में आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री अनुतिन चर्णविराकुल की सरकार उन विदेशी देशों पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है जिन पर थाइलैंड के वीजा-फ्री सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल करके गैरकानूनी गतिविधियां करने का आरोप है।

संपादकीय

पात्र से अपात्र कैसे हुईं लाखों महिलाएं?

कोई भी सरकारी योजना शुरू करने से पहले लाभार्थियों को केंद्र में रखकर उसके लिए नियम-शर्तें तय की जाती हैं। इसी आधार पर पात्र लोगों का चयन कर संबंधित योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाता है। मगर किसी योजना को चुनाव से ठीक पहले लागू किया जाए और उसी सरकार के फिर से राज्य में कमान संभालने के बाद अगर बड़ी संख्या में लोगों को पात्रता की सूची से बाहर कर दिया जाए, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' से नब्बे लाख से ज्यादा महिलाओं को बाहर कर दिया है। यानी इन महिलाओं को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब वे या तो पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई हैं या फिर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा न कर पाने की वजह से उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या इस योजना में नई नियमावली जोड़ी गई है! अगर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि जो महिलाएं पहले पात्र थीं, अब वे अपात्र हो गई हैं?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले जून, 2024 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएं प्रति माह डेढ़ हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना में राज्य की 2.4 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया था। मगर अब फिर से सत्तासीन हुई महायुति सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत लाखों महिलाओं के नाम इस योजना से बाहर कर दिए हैं। सवाल है कि शुरू में इन महिलाओं को किस आधार पर पात्र घोषित किया गया था? क्या तब दस्तावेजों की जांच सही ढंग से नहीं की गई थी या फिर इसके पीछे इससे चुनावी लाभ उठाने की मंशा थी?

हालांकि सरकार का दावा है कि पचास से पचपन लाख महिलाएं तय समय सीमा में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कम शिक्षित और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं ई-केवाईसी की बारीकियों को नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कार्य में उनकी सहायता के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं।

राज्य सरकार के मुताबिक, लगभग बारह लाख महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय इस योजना की निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। जबकि पैंतालीस लाख से अधिक महिलाएं पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुकी थीं। हैरत की बात तो यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब चौदह हजार पुरुष भी महिला बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन्हें अब बाहर कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं में पात्रता मानदंडों की जांच में किस कदर लापरवाही बरती जाती है। यही नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी राज्य सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट के मुकाबले साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए। साथ ही जमा खातों में हजारों करोड़ रुपए रखने और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को भी उजागर किया गया है। ऐसे में अब यह मांग की जा रही है कि इस योजना की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके।

यूपी में वारदात को अंजाम देने से पहले कानून से खौफ खाते हैं अपराधी?

उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा रहा है कि उसने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिस स्तर पर सख्ती और कार्रवाई की है, उसकी वजह से राज्य की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बना है और कहीं भी आने-जाने में उन्हें किसी तरह के असुरक्षा-भाव से नहीं गुजरना पड़ता। सरकार के इस तरह के दावे निश्चित रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राज्य में सरकार और पुलिस का प्रभाव वास्तव में इतना असरकारी है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी कानून से खौफ खाते हैं! गौरतलब है कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर में सात वर्षीय बच्ची का शव मिला, जिसकी हालत देख कर उससे बलात्कार के बाद उसकी हत्या की आशंका भी जताई गई है। खबर के मुताबिक, वहीं मजदूरी कर रहे परिवार की उस बच्ची को बहला-फुसला कर ले जाया गया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के अलावा भी हाल के दिनों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार या उनकी हत्या के अन्य मामले सामने आए और न्याय की मांग के साथ लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। यह छिपा नहीं है कि आए दिन राज्य सरकार अपना प्रभाव साबित करने के उद्देश्य से अपराध को खत्म कर देने की दुहाई देती रहती है। यह भी दावा किया जाता रहता है कि कानून के डर से अब अपराधी राज्य छोड़ कर भाग चुके हैं। अगर सरकार के दावे सही हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता और वे महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे? यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार आपराधिक घटनाओं की संख्या थानों में दर्ज आंकड़ों के मुकाबले वास्तव में कहीं ज्यादा होती हैं। कहने को महिलाओं के लिए राज्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कानून से लेकर हर स्तर पर चौकसी बरतने और हेल्पलाइन की व्यवस्था करने जैसे उपाय किए गए हैं। मगर सच्चाई यह है कि सरकारी दावों के समांतर अभी भी ऐसा तंत्र सक्रिय करने की जरूरत है, जो महिलाओं के लिए वास्तव में सुरक्षित माहौल बना सके।

आज का कार्टून

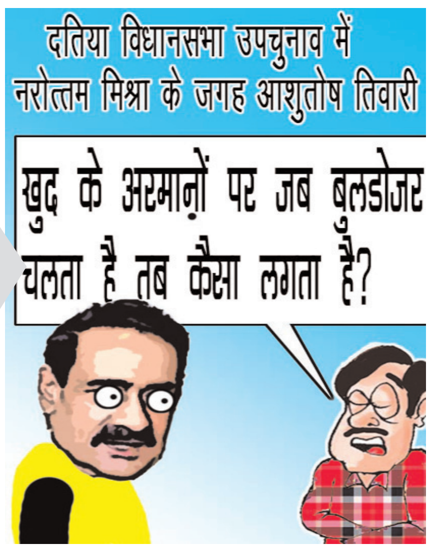
दतिया विधानसभा उपचुनाव में
नरोत्तम मिश्रा के जगह आशुतोष तिवारी
खुद के अरमानों पर जब बुलडोजर चलता है तब कैसा लगता है?

आखिर कब रूकेगी सीवर सफाई में मौतें

अखिलेश आर्येंदु

समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, स्वार्थवादी प्रवृत्ति और न्याय के अभाव में उपेक्षित वर्ग को कई तरह की विकट परिस्थितियों एवं त्रासदियों का सामना करना पड़ता है। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ ऐसे कार्य हैं, जो आज भी एक खास वर्ग के जिम्मे हैं। हाथ से मैला साफ करने का कार्य भी इनमें से एक है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक में गंदे नाले, सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी श्रमिक की मौत हो जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मगर, ऐसे मामले विरले ही होते हैं, जिनमें संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की भावना के अनुरूप किसी संस्था, ठेकेदार या संबंधित व्यक्ति को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय के कठघरे में लाया गया हो और उसे दंडित किया गया हो। यह उस भारतीय समाज की सच्चाई है, जो स्वयं को शिक्षित, समझदार और प्रगतिशील मानता है।

देश में हर साल बड़ी संख्या में हाथ से मैला साफ करने वाले श्रमिकों की मौत जहरीली गैसों या आक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है। मगर ज्यादातर मामलों में इसे दुर्घटना कह कर हर स्तर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये श्रमिक समाज के उस वर्ग से आते हैं, जो अब तक उपेक्षित हैं। ऐसा लगता है कि इनके प्रति समाज में सम्मान, संवेदना और सहानुभूति की कोई जगह नहीं है।

यही वजह है कि कानून की नजर में प्रतिबंधित एवं जोखिमपूर्ण कार्य में भी इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा के झोंक दिया जाता है। केंद्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर अंकुश लगाने और गंदे नालों एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1993 में कानून बनाया था। इसके बाद वर्ष 2013 में हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिशेध तथा पुनर्वास अधिनियम बनाया गया। इसके तहत हाथ से मैला उठाने, सीवर या सेप्टिक टैंक में असुरक्षित तरीके से सफाई कराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही ऐसे कार्य में लगे लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया। मगर ये कानून आज भी जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं।

सवाल यह है कि आए दिन सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस या आक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा? जब कानून में इस तरह के कार्यों के लिए मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, तो फिर श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के इस कार्य में क्यों झोंक दिया जाता है? इस दौरान जब किसी श्रमिक की मौत हो जाती है, उसके लिए किसी की जिम्मेदारी या जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पाती है! जाहिर है कि ये श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई राजनीतिक दल, मजदूर संघ और यहां तक गैर सरकारी संगठन भी आगे नहीं आते। करीब एक दशक पहले सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में वर्ष 2014 में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीवर, नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई को पूरी तरह यांत्रिक किया जाए और सभी पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अदालत के इस आदेश का पालन कितनी गंभीरता से हो रहा है इसका अंदाजा आए दिन सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत से जुड़ी घटनाओं से लगाया जा सकता है। यानी नाले, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य आज भी मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से कराया जा रहा है, जिससे हर साल बड़ी संख्या में जहरीली गैसों या आक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। चिंता की बात यह है कि न तो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून का पूरी तरह से पालन हो पा रहा है और न ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। ऐसे में इस तरह से होने वाली श्रमिकों की मौत को कैसे रोका जाए, यह एक बड़ा सवाल है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कार्य की परिस्थितियों को लेकर एक कानून बनाया था। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता नामक इस कानून में काम के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा, खतरनाक गैसों से बचाव और उन मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है, जिनके जरिए आसानी से नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई की जा सकती है। सवाल यह है कि कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद सीवर की सफाई में आज भी मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल के बजाय इस कार्य को बिना सुरक्षा के श्रमिकों से ही क्यों कराया जा रहा है? कानून का उल्लंघन किस तरह हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण पिछले माह दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से तीन श्रमिकों की मौत हो जाने की घटना है। इसे भी सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया गया।

दरअसल, सीवर, नाले और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य अक्सर ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है। वे मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से यह कार्य करवाते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े। वे नियम-कानून की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस जोखिम भरे कार्य में जब किसी सफाईकर्मी की मौत हो जाती है, तो ज्यादातर मामलों में ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती भी है, तो नाममात्र के लिए। ऐसे मामलों में दर्ज प्राथमिकी में इतनी कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं कि दोषी मामूली दंड पाकर छूट जाता है और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाती है।

विडंबना यह है कि ऐसे श्रमिकों की सफाई कार्य के दौरान मौत के आंकड़े भी वास्तविकता से बहुत कम दर्ज हो पाते हैं। दरअसल, नाले, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले श्रमिकों की मौत के जो आंकड़े सरकारें जारी करती हैं, ये वे मामले होते हैं, जो पुलिस प्राथमिकी के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं। इसलिए वास्तविक आंकड़ों का सही पता नहीं चल पाता है। सफाई मजदूर संगठनों की मानें तो सरकारी आंकड़े की अपेक्षा वास्तविक आंकड़े में कई गुना का अंतर है। इससे साफ है कि इस तरह के हादसों में जान गंवाने वाले कई श्रमिकों के परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती है।

ऐसे में अगर कमाई करने वाले इकलौते व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। मगर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे दूसरे लोगों को सबक मिल सके। सवाल है कि मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग या फिर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठन क्या कभी ऐसे श्रमिकों की मौत को लेकर मुखर होंगे? जब बात अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की आती है, तो समाज के हर वर्ग के उत्थान का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की संवेदनाएं आखिर कहां गुम हो जाती हैं!

> दरअसल, सीवर, नाले और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य अक्सर ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है। वे मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से यह कार्य करवाते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े। वे नियम-कानून की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस जोखिम भरे कार्य में जब किसी सफाईकर्मी की मौत हो जाती है, तो ज्यादातर मामलों में ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती भी है, तो नाममात्र के लिए। ऐसे मामलों में दर्ज प्राथमिकी में इतनी कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं कि दोषी मामूली दंड पाकर छूट जाता है और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाती है। विडंबना यह है कि ऐसे श्रमिकों की सफाई कार्य के दौरान मौत के आंकड़े भी वास्तविकता से बहुत कम दर्ज हो पाते हैं। दरअसल, नाले, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले श्रमिकों की मौत के जो आंकड़े सरकारें जारी करती हैं, ये वे मामले होते हैं, जो पुलिस प्राथमिकी के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं।

भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन...

> भारत की रेल व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। यह सिर्फ एक नई रेलगाड़ी की शुरुआत नहीं, बल्कि भारतीय रेल के हरित परिवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक पहल भी होगी। हरियाणा के जींद से चलने वाली यह रेलगाड़ी देश को स्वच्छ और कम प्रदूषण वाली परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास है। हालांकि इस उपलब्धि के साथ कई तकनीकी और आधारभूत चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जिनका समाधान भविष्य की सफलता तय करेगा।

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को जींद दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को पूरे कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है और वह स्वयं तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले भाटिया मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, पेयजल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाने के साथ हरियाणा की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

उधर, रेलवे के अनुसार यह रेलगाड़ी दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ियों में शामिल होगी। इसमें आठ यात्री डिब्बे और दो पावर कार होंगे। लगभग दो हजार चार सौ किलोवाट क्षमता वाली यह रेलगाड़ी एक बार में कम से कम छह सौ बयासी यात्रियों को लेकर चल सकेगी। यह जींद और सोनीपत के बीच लगभग नवासी किलोमीटर लंबे मार्ग पर अधिकतम पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। प्रतिदिन दो फेरे लगाएगी और कुल तीन सौ छप्पन किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान लगभग तीन सौ किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत होने का अनुमान है। छुट्टियांव मौसमी आयोजन

कैसे चलेगी हाइड्रोजन रेलगाड़ी यदि इसकी बात करें तो आपको बता दें कि सामान्य विद्युत रेलगाड़ियां ऊपर लगे तारों से मिलने वाली विद्युत धारा पर निर्भर रहती हैं, लेकिन हाइड्रोजन रेलगाड़ी की कार्यप्रणाली पूरी तरह अलग है। इसमें हाइड्रोजन और वायु से प्राप्त ऑक्सीजन को ईंधन कोश में मिलाकर विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। यही ऊर्जा रेलगाड़ी को गति देती है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है और मुख्य उपोत्पाद के रूप में केवल जल बनता है। यही कारण है कि इसे स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

भारतीय रेल की इस परियोजना में प्रत्येक पावर कार में चार एकीकृत पावर पैक लगाए गए हैं। इनमें हाइड्रोजन ईंधन कोश और लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी का संयोजन किया गया है। प्रत्येक पावर पैक तीन सौ किलोवाट ऊर्जा देगा, जिसमें एक सौ पंद्रह किलोवाट ईंधन कोश और एक सौ पचासी किलोवाट बैटरी से प्राप्त होगी। चारों पावर पैक मिलकर बारह सौ किलोवाट क्षमता उपलब्ध कराएंगे। चूंकि रेलगाड़ी में दो पावर कार हैं, इसलिए कुल क्षमता चौबीस सौ किलोवाट अर्थात लगभग तीन हजार दो सौ अश्वशक्ति होगी। यह क्षमता समान दूरी तय करने वाली सामान्य विद्युत या डीजल बहु इकाई रेलगाड़ियों के बराबर मानी जा रही है।

H2
Powered
Clean Mobility

ईंधन कोश और बैटरी के संतुलित तालमेल के बारे में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ईंधन कोश लगातार एक समान ऊर्जा देता है। इसलिए जब रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, तब शुरुआती अधिक ऊर्जा की आवश्यकता ईंधन कोश से पूरी होती है। जैसे ही रेलगाड़ी गति पकड़ती है और ऊर्जा की मांग बढ़ती है, बैटरी अतिरिक्त शक्ति उपलब्ध कराती है। दूसरी ओर, जब रेलगाड़ी की गति कम होती है या वह किसी स्टेशन के पास पहुंचती है, तब अतिरिक्त ऊर्जा से बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है। इस व्यवस्था से पूरी यात्रा के दौरान बैटरी लगभग अस्सी प्रतिशत तक भरी रहती है और ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहती है।

हम आपको यह भी बता दें कि हाइड्रोजन रेल तकनीक अभी दुनिया के चुनिंदा देशों तक ही सीमित है। इस तकनीक का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 2016 में बर्लिन में हुआ था। बाद में जर्मनी ने दो डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी शुरू की, जिसे दुनिया की पहली यात्री हाइड्रोजन रेलगाड़ी माना गया। इसके बाद जापान, चीन और अमेरिका ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि अभी तक इन रेलगाड़ियों का उपयोग मुख्य रूप से छोटी दूरी की सेवाओं तक सीमित है, क्योंकि तकनीक अभी विकास के दौर में है।

साथ ही हाइड्रोजन रेलगाड़ी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव को एक बार माना जाता है, जबकि हाइड्रोजन को दो सौ से पांच सौ बार के अत्यधिक दबाव पर संग्रहित करना पड़ता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसके भंडारण और परिवहन के लिए अत्यंत सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक होती है। सरकारीएजेंसियां

हम आपको बता दें कि रेलवे ने जींद में तीन हजार किलोग्राम क्षमता वाला ईंधन भरने का केंद्र बनाया है। यहां हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए विशेष शीतलन संयंत्र लगाया गया है, जो ईंधन भरने के दौरान हाइड्रोजन का तापमान शून्य से पंद्रह डिग्री नीचे तक बनाए रखता है। कम तापमान पर हाइड्रोजन द्रव अवस्था के निकट पहुंचती है, जिससे सुरक्षित और प्रभावी ईंधन आपूर्ति संभव होती है।

बहरहाल, भारतीय रेल के लिए यह परियोजना केवल एक नई रेलगाड़ी का संचालन नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की आधारशिला है। यदि हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और लागत से जुड़ी चुनौतियों का सफल समाधान निकलता है, तो आने वाले वर्षों में यह तकनीक डीजल आधारित रेल सेवाओं का प्रभावी विकल्प बन सकती है। फिलहाल यह प्रयोग भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करता है, जिन्होंने पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। अब सबसे बड़ी परीक्षा इस तकनीक को सुरक्षित, किफायती और व्यापक स्तर पर सफल बनाकर दिखाने की है।

968 दिन बाद लौटे बुमराह का कमाल

- जडेजा और अगरकर को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में लौटते ही कमाल कर दिया। पहले 4 ओवर में सिर्फ 8 रन और फिर पांचवें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उन्होंने इस विकेट के साथ वनडे इंटरनेशनल में अपने 150 विकेट पूरे किए। साथ ही वह इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। जसप्रीत बुमराह ने अपने 90वें मैच और 89वीं पारी में 150वां विकेट लिया और सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बने। जबकि इंग्लैंड में उनका यह 31वां वनडे विकेट था। रविंद्र जडेजा (30) को पीछे छोड़ते हुए इस मामले में बुमराह नंबर 1 भारतीय गेंदबाज बने। भारत के लिए सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। कुलदीप यादव इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सबसे कम गेंदों के लिहाज से भी बुमराह सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय हैं।

भारत के लिए सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज

- मोहम्मद शमी: 80वां मैच
- कुलदीप यादव: 88वां मैच
- जसप्रीत बुमराह: 90वां मैच
- अजीत अगरकर: 97वां मैच
- जहीर खान: 103वां मैच

सबसे कम गेंदों पर 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय

- 4070 गेंद: मोहम्मद शमी
- 4513 गेंद: कुलदीप यादव
- 4605 गेंद: जसप्रीत बुमराह
- 5027 गेंद: अजीत अगरकर
- 5131 गेंद: इरफान पठान

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

- 31 विकेट: जसप्रीत बुमराह*
- 30 विकेट: रविंद्र जडेजा
- 28 विकेट: भुवनेश्वर कुमार
- 27 विकेट: मदन लाल
- 26 विकेट: मोहम्मद शमी

968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में लौटे

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना इससे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच 19 नवंबर 2023 को खेला था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने के बाद अब बुमराह की वनडे टीम में वापसी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह इंजरी के कारण खेल नहीं पाए थे। ऐसे में अब 968 दिन बाद 14 जुलाई 2026 को लौटते ही बुमराह ने दो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लीं। बुमराह ने अपने पहले पांच ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और एक विकेट हैरी ब्रूक का झटका। उन्होंने 2016 में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

पीवी सिंधु की दमदार जीत

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने बीच में छोड़ा मैच, कोच ने चीन ओपन से भी हटने की पुष्टि की

नई दिल्ली। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए मंगलवार 14 जुलाई 2026 का दिन मिला-जुला रहा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिंग चिंग को सीधे गेमों में हराकर महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला-तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने सीधे गेमों में जीत हासिल करके दूसरे राउंड में जगह बनाई।

वहीं, पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की विश्व नंबर चार जोड़ी सात्विक के कंधे की चोट के कारण पहला गेम हारने के बाद मुकाबले से हट गई। चोट की वजह से भारतीय जोड़ी अगले सप्ताह होने वाले चीन ओपन में भी हिस्सा नहीं लेगी और अब उसका पूरा ध्यान विश्व चैंपियनशिप से पहले फिटनेस हासिल करने पर रहेगा।

सात्विक को लगेगा चोट से उबरने में समय

टैम किम हर ने कहा, 'सात्विक को ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा। विश्व चैंपियनशिप से पहले हमें कम से कम 4 सप्ताह का समय मिलेगा, जिससे हम पुरानी लय हासिल कर सकते हैं।' इससे पहले विश्व रैंकिंग में नंबर 10 पर काबिज पीवी सिंधु ने अपने सहज खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले दौर में विश्व रैंकिंग में नंबर 37 पर काबिज वोंग को हराया।

शुरुआत से ही बनाया दबदबा

पीवी सिंधु ने शुरुआत से ही खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और रैलियों की गति को नियंत्रित करते हुए 7-4 की बढ़त हासिल की। हालांकि, वोंग ने संघर्ष जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलतियों ने भारतीय खिलाड़ी को लगातार आगे बढ़ने का मौका दिया। पीवी सिंधु ने इंटरवल तक 11-6 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी रैलियों में सहज दिख रही थीं और उन्होंने अपने स्ट्रोक्स को प्रभावी ढंग से लगाकर अपनी बढ़त को 14-9 तक पहुंचा दिया। उनके बैकहैंड नेट ड्रिबल, ड्रॉप शॉट और हाफ-स्मैश सटीक रहे। एक सीधे शॉट से पीवी सिंधु को सात गेम पॉइंट मिले और उन्होंने पहला गेम अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु ने दूसरे गेम में भी शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया और मलेशिया की खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ी ने जल्द ही 8-2 की बढ़त हासिल की। पीवी सिंधु इंटरवल तक 11-3 से आगे थीं। इसके बाद भी उन्होंने बड़ा अंतर बनाए रखा और फिर 10 मैच पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे मैच पॉइंट पर मैच अपने नाम किया।

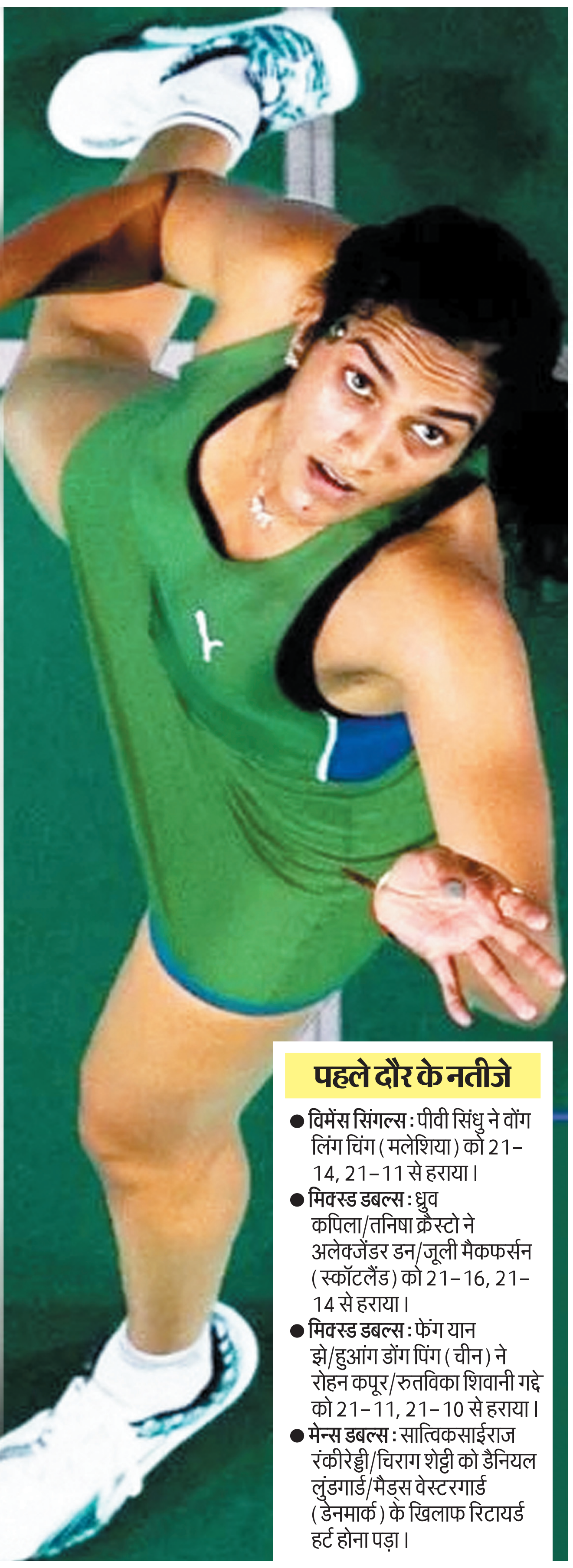

पहले दौर के नतीजे

- **विमेंस सिंगल्स :** पीवी सिंधु ने वोंग लिंग चिंग (मलेशिया) को 21-14, 21-11 से हराया।
- **मिक्स्ड डबल्स :** ध्रुव कपिला/तनिषा क्रैस्टो ने अलेक्जेंडर डन/जूली मैकफर्सन (स्कॉटलैंड) को 21-16, 21-14 से हराया।
- **मिक्स्ड डबल्स :** फेंग यान झे/हुआंग डोंग पिंग (चीन) ने रोहन कपूर/रुतविका शिवानी गद्दे को 21-11, 21-10 से हराया।
- **मेन्स डबल्स :** सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी को डैनियल लुंडगार्ड/मैड्स वेस्टरगार्ड (डेनमार्क) के खिलाफ रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा।

स्पेन ने फ्रांस को हराया

- 16 साल बाद फाइनल में बनाई जगह; एम्बाप्पे के खिलाफ यामाल का रिकॉर्ड कायम

नई दिल्ली। स्पेन ने साबित कर दिया है कि वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे मजबूत टीमों में से एक क्यों हैं। स्पेन ने डलास स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में मजबूत फ्रांस को 2-0 हराकर फाइनल में जगह बनाई। लुइस डे ला फुएंते की कप्तानी में स्पेनिश टीम के इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही वे 96 सालों में दूसरी और 44 सालों में पहली ऐसी टीम बन गई हैं जिसने वर्ल्ड कप में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की।

दूसरी बार फाइनल में पहुंचा स्पेन

स्पेन ने यूरो 2024 जीता और मौजूदा यूरोपियन चैंपियन के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। जब वे पिछली बार 2010 में फाइनल में पहुंचे थे जिसे उन्होंने जीता था तब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन भी था जिसने 2010 में ट्रॉफी जीती थी। अब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन के तौर पर दो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। वेस्ट जर्मनी ऐसा करने वाली पहली टीम थी और उसने साल 1972 और 1980 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 और 1982 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर स्पेन यह टूर्नामेंट जीतता है, तो वह मौजूदा यूरो चैंपियन के तौर पर दो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। जर्मनी ने 1972 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 का टूर्नामेंट जीता था।

- **स्पेन को 2-0 से मिली जीत, मिकेल-पोरो ने किए गोल-** सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा फ्रांस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक अटैक करने वाली टीम के तौर पर फाइनल में पहुंचा था और उसने 16 गोल किए थे। हालांकि स्पेन की डिफेंसिव ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमाए रखा और फ्रांस को गोल करने का कोई मौका तक नहीं दिया। मिकेल ओयारजाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी से स्पेन के लिए पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल करके मैच का नतीजा तय कर दिया।

- बर्मिंघम में 12 साल बाद जीता भारत
- सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया

अक्षर पटेल ने गेंद और बल्ले से किया कमाल

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत अपने नाम कर ली है। बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया यह मुकाबला टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बर्मिंघम में 12 साल के इंतजार के बाद भारतीय टीम ने वनडे मैच जीता है। अक्षर पटेल इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो साबित हुए। उन्होंने गेंद के बाद बल्ले से कमाल किया और शानदार अर्धशतकी पारी खेली। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में 9.5 ओवर में 4 विकेट लेकर 62 रन दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी में उन्होंने टीम को तब संभाला जब उनकी बल्लेबाजी की खास जरूरत थी। अक्षर ने 52 गेंद पर नाबाद 57 रन की पारी खेली।

12 साल बाद बर्मिंघम में जीत

भारत ने इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 46 वनडे मैच खेले हैं। इंग्लैंड की सरजमीं पर भारत को यह 19वीं जीत मिली है। जबकि इंग्लैंड की टीम ने 23 मैच भारत के खिलाफ अपने घर पर जीते हैं। भारत की बर्मिंघम में आखिरी जीत 2014 में अंग्रेज टीम के खिलाफ आई थी। इस मैदान पर इंग्लैंड की भी यह आखिरी हार थी। उसके बाद से यहां इंग्लैंड लगातार सात वनडे मैच जीता था। अब फिर से भारत ने इंग्लैंड को यहां हराया है। भारतीय टीम से विदा होना चाहता है गंभीर का साथी, ब्बष्टष्ढ्ढ को दे चुका है जानकारी भारत ने 2014 से 2026 के बीच यहां एक भी मैच नहीं जीता था।

शुभमन गिल बीच मैच गए मैदान से बाहर

80 रन बनाकर हुए रिटायर्ड हर्ट

नई दिल्ली। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 48 रन पर दो विकेट के बाद उन्होंने उपकप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी पूरी की।

75 गेंद पर गिल 80 रन बना चुके थे लेकिन अचानक उन्हें मैच के बीच ही मैदान से बाहर रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ा। उनके वापस लौटने से भारत को बड़ा झटका लगा। मैच के पहले ओवर से बेहतरीन लय में नजर आ रहे कप्तान शुभमन गिल का रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

शुभमन गिल को क्या हुआ?

शुभमन गिल पिछले 2,3 ओवर से लगातार लंगड़ाते दिख रहे थे। उन्होंने एक स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें खिंचाव महसूस हुआ। वह दिक्कत में भी दिखे और फिर फिजियो मैदान पर आए। काफी देर इलाज के बाद फैसला लिया गया कि वह बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे। वह वापस बल्लेबाजी करने उतर पाएंगे या नहीं इस पर नए अपडेट का इंतजार है।

रोहित-विराट दोनों फ्लॉप

पहले वनडे में 'RoKo' फैंस निराश

नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित 21 गेंद पर 11 और विराट 6 गेंद पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लिहाजा इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के पहले मैच में रोको फैंस को निराश लौटना पड़ा। इतना ही नहीं कुछ ऐसे आंकड़े और कमजोरियां भी दोनों खिलाड़ियों की सामने आईं जिससे टीम इंडिया की टेंशन भी बढ़ गई।

रोहित शर्मा का वनडे वर्ल्ड कप 2023 से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक पहले 10 ओवर में स्ट्राइक रेट 122.56 और औसत 67.41 का था। मगर अक्टूबर 2025 से अब तक रोहित का स्ट्राइक रेट पहले 10 ओवर में गिरकर 86.12 का हो गया है और औसत भी कम होकर 44.50 हो गया है। दूसरी ओर विराट कोहली की बात करें तो लंबे समय बाद वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे। अफगानिस्तान सीरीज में वह टीम का हिस्सा नहीं थे और इंजरी के कारण बाहर थे।

टीम इंडिया के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली का भी आगाज अच्छा नहीं रहा। वह जोफ्रा आर्चर की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। जनवरी 2023 से अब तक यह चौथा मौका था जब पेस बॉलर के खिलाफ विराट पगबाधा आउट हुए। जबकि उससे पहले 10 साल में वह सिर्फ एक बार ही तेज गेंदबाज के सामने इस तरह आउट हुए थे। यह रोहित और विराट के आंकड़े अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं।

केएल राहुल का शानदार कैच

बल्लेबाज भी हुआ हैरान

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने जलवा बिखेरा है। इस मुकाबले में 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में लौटे जसप्रीत बुमराह ने अंग्रेज बल्लेबाजों की नाक में दम किया और एक विकेट लेते ही दो रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके बाद 706 दिन के इंतजार के बाद भारत की वनडे टीम में लौटे ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भी कमाल की गेंदबाजी की और केएल राहुल के शानदार कैच की बदौलत उन्हें विकेट भी मिला। शिवम दुबे ने अपने पहले 5 ओवर के स्पेल में 21 रन दिए और एक विकेट लिया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे विल जैक्स को पवेलियन भेजा। केएल राहुल ने विकेट के पीछे अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लपका। जैक्स 19 गेंद पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए त्राधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670